● वर्ष-2
● अंक-235
रायपुर, बुधवार
24 मई 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

samacharpacheesa@gmail.com

सिडनी में दिखा भारत, मोदी संग सेल्फी लेने की होड़

ब्रिस्बेन में खुलेगा वाणिज्य दूतावास, लखनऊ और जयपुर का भी किया जिक्र

सिडनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सिडनी के कुडोस बैंक एरिना में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी को देख लोग "भारत माता की जय", "वंदे मातरम" और "मोदी, मोदी" के नारे लगा रहे थे। जब पीएम मोदी लोगों के बीच आए तो लोग उनके संग सेल्फी लेने उमड़ पड़े। पीएम मोदी के संबोधन से पहले ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने लोगों को संबोधित किया और प्रधानमंत्री मोदी को "बॉस" कहा। अल्बनीस ने कहा कि उनकी लोकप्रियता अमेरिकी गायक-गीतकार ब्रूस स्प्रिंगस्टीन से अधिक है। सिडनी में कुडोस बैंक एरिना में कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ सेल्फी लेने के लिए लोग उमड़ पड़े। पीएम मोदी लगातार लोगों से हाथ मिला थे साथ ही कुछ लोगों को उनकी डायरी में ऑटोग्राफ भी दिया। जो लोग दूर थे पीएम को देखकर मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे, इस दौरान पीएम मोदी ने दोनों हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया।

सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री भारत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के पास सामर्थ्य की कमी नहीं है। भारत के पास संसाधनों की भी कमी नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री भारत में है। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि आप सब ने भी आजादी का अमृत महोत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाया है। हमारे क्रिकेट के रिश्ते को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। क्रिकेट की फील्ड पर मुकाबला जितना रोचक होता है उतनी ही गहरी हमारी ऑफ द फील्ड दोस्ती है। पिछले साल जब महान क्रिकेटर शेन वार्न का निधन हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के साथ कोटि-कोटि भारतीयों ने भी शोक मनाया। ये ऐसा था जैसे हमने अपना कोई खो दिया।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी में जिस देश ने दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन कार्यक्रम किया वो भारत है, आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है, आज भारत दुनिया में नंबर 1 स्मार्ट फोन डेटा उपभोक्ता है.......अब जो देश अगले 25 साल में विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है वो भारत है।

लोगों से खचाखच भरा था स्टेडियम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग सुनने को मौजूद थे। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा था। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगले 25 साल में विकसित होने के लक्ष्य के साथ जो देश आगे बढ़ रहा है वो देश भारत है। आज आईएमएफ भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का उज्ज्वल बिन्दु मानता है। वर्ल्ड बैंक का विश्वास है कि ग्लोबल हेडविंड्स को अगर कोई चुनौती दे रहा है तो वो भारत है।

संबोधन की बड़ी बातें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में सोमवार को ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने सिडनी के कुडोस बैंक एरिना में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। ब्रिस्बेन में वाणिज्य दूतावास के शुभारंभ का एलान किया। भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों से लेकर क्रिकेट तक पर बात की। जहां उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान भारत द्वारा चलाए गए सबसे बड़े वैक्सिनेशन अभियान का जिक्र करके भारत के बढ़ते कद को दुनिया को दिखाया वहीं, 2014 में के वादे का हवाला देकर बिना नाम लिए कांग्रेस पर तंज भी कसा।

पीएम मोदी की तारीफ में प्रधानमंत्री अल्बानीस ने पढ़े कसीदे

प्रधानमंत्री अल्बानीस ने कहा कि आखिरी बार मैंने इस मंच पर किसी को ब्रूस स्प्रिंगस्टीन के रूप में देखा था और उन्हें वह स्वागत नहीं मिला जो प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी द बॉस हैं। आगे उन्होंने कहा कि भारत यात्रा मेरे लिए अविस्मरणीय क्षणों से भरी है, गुजरात में होली मनाना, दिल्ली में महात्मा गांधी के लिए पुष्पांजलि अर्पित करना... मैं भारत में जहां भी गया, मैंने ऑस्ट्रेलिया और भारत के लोगों के बीच एक गहरा संबंध महसूस किया। यदि आप भारत को समझना चाहते हैं, तो ट्रेन और बस से यात्रा करें।

ब्रिस्बेन में खुलेगा भारत का नया कॉन्सुलेट

एरिना में पीएम मोदी ने नमस्ते ऑस्ट्रेलिया से अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि एक समय था जब कहा जाता था कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3ष्ट (कॉमनवेल्थ, क्रिकेट, करी) पर आधारित है। उसके बाद कहा गया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का संबंध 3ष्ट (डेमोक्रेसी, डायसपोरा, दोस्ती) पर आधारित है। इसके बाद में कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का संबंध 3श्व (एनर्जी, इकोनॉमी, एजुकेशन) पर आधारित है। लेकिन भारत-ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक संबंधों का विस्तार इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इस दौरान पीएम मोदी ने ब्रिस्बेन में भारत का नया कॉन्सुलेट (वाणिज्य दूतावास) खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि इसकी मांग काफी समय से की जा रही थी, जिसके बाद यह फैसला किया गया है।

लखनऊ की चाट, जयपुर की मिठाई का जिक्र

पीएम मोदी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के लोग इतने विशाल दिल वाले हैं। इतने सच्चे और अच्छे हैं कि भारत की इस विविधता को खुले दिल से स्वीकारते हैं। यही वजह है कि यहां के पैरमाटा शहर में परमात्मा चौक बन जाता है। विग्रम स्ट्रीट भी विक्रम स्ट्रीट के तौर पर मशहूर हो जाती है और हैरिस पार्क लोगों के लिए हरीश पार्क हो जाता है। हैरिस पार्क में जयपुर स्वीट्स की जलेबी, चाट, इसका तो कोई जवाब नहीं है। आप लोग मेरे मित्र अल्बानीज को भी कभी वहां ले जाइएगा।

इन दिनों

✍ अजय बग्गा

नोटबंदी 2.0 से जमाखोरों को लगेगा झटका

भारतीय रिजर्व बैंक ने बीते दिनों घोषणा की कि वह दो हजार रुपये के सभी नोटों को प्रचलन से वापस ले रहा है और आगामी 30 सितंबर तक इसे बैंक से बदला जा सकता है। अभी जो दो हजार रुपये के 10.8 फीसदी नोट प्रचलन में हैं, वे किनके पास हैं? रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक 33.5 लाख करोड़ रुपये के नोट प्रचलन में थे। बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उनमें से 1.03 लाख करोड़ रुपये बैंकों के पास हैं। इसलिए बैंकों के पास प्रचलित नोटों का मात्र तीन फीसदी से थोड़ा ज्यादा हिस्सा है, बाकी करीब 97 फीसदी नोट आम लोगों के पास हैं। यानी जनता के पास 3.51 लाख करोड़ रुपये के बराबर दो हजार रुपये के बैंक नोट होंगे। रियल एस्टेट, निर्माण, थोक व्यापार और ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी नकदी का उपयोग प्रचलित है। इसलिए इनमें से अधिकांश दो हजार रुपये के नोट इन क्षेत्रों के कारोबारियों के पास होंगे। बड़ा सवाल यह है कि यह कदम क्यों उठाया गया और वह भी इस समय क्यों। मार्च, 2018 से बैंकों को 2,000 रुपये के नोट जारी न करने का निर्देश दिया गया था। जब इन नोटों को बैंकों में जमा किया गया, तो इन्हें चुपचाप रिजर्व बैंक को वापस भेज दिया गया और अर्थव्यवस्था में पुन: परिचालित नहीं किया गया। मार्च, 2018 के बाद 2,000 रुपये के नए नोट नहीं छापे गए। इस तरह दो हजार रुपये के नोटों का प्रचलन घट गया। रिजर्व बैंक ने इसके पीछे तीन कारण गिनाए हैं-पहला, इन नोटों का उपयोग दैनिक लेन-देन में नहीं किया जाता है। दूसरा, जरूरतें पूरी करने के लिए छोटे मूल्यवर्ग के नोटों की उपलब्धता पर्याप्त है और तीसरा, नकदी के उपयोग को यूपीआई और डिजिटल भुगतान के व्यापक उपयोग द्वारा पूरा किया जा रहा है। नवंबर, 2016 में रातोंरात 86 फीसदी भारतीय मुद्रा के विमुद्रीकरण के बाद से अर्थव्यवस्था की प्रगति को देखें, तो 12 मई, 2023 तक नोटों का प्रचलन वास्तव में 17.74 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 34.58 लाख करोड़ रुपये हो गया है। यानी %कैशलेस% अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के बजाय, अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रवाह पिछले साढ़े छह वर्षों में दोगुना हो गया है। भले ही छोटे लेन-देन यूपीआई और ई-कॉमर्स जैसे डिजिटल भुगतान नेटवर्क में स्थानांतरित हो गए हैं, पर अर्थव्यवस्था में नकदी में लगभग सौ फीसदी वृद्धि को देखते हुए यह स्पष्ट है कि काले धन के खिलाफ लड़ाई को और अधिक कठोर तथा नवीन बनाने की आवश्यकता होगी। यह रिजर्व बैंक का एक सुविचारित कदम है, जिससे दो हजार रुपये के नकदी जमाखोरों को झटका लगेगा। अर्थव्यवस्था में काले धन के खतरे को कम करने के लिए भ्रष्ट और आपराधिक तत्वों से सख्ती से निपटने की जरूरत है।

2000 का नोट बदलने की कवायद 'नोटबंदी' नहीं

■ **आरबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में रखा अपना पक्ष, फैसला सुरक्षित**

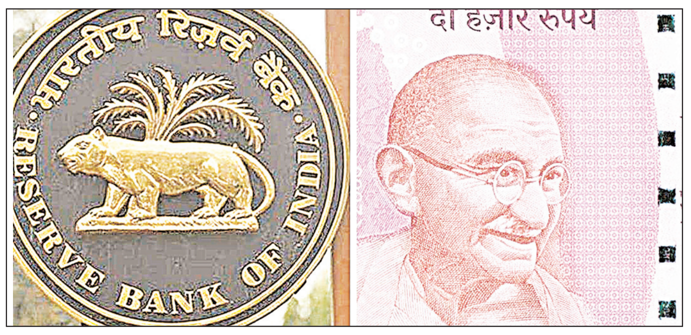

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि 2000 रुपये के नोटों को वापस लेना नोटबंदी नहीं है, बल्कि एक वैधानिक कवायद है। आरबीआई ने कहा कि दो हजार के नोट परिचालन सुविधा के लिए शुरू किए गए थे। अदालत वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया है कि आरबीआई और एसबीआई की ओर से बिना सबूत के 2000 रुपये के बैंक नोटों को बदलने की अधिसूचना मनमानी है और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाए गए कानूनों के खिलाफ है।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि वह वकील की जनहित याचिका पर उचित आदेश पारित करेगी। अदालत ने कहा, हम इस पर गौर करेंगे। हम उचित आदेश पारित करेंगे। उपाध्याय ने स्पष्ट किया कि वह 2000 रुपये के बैंक नोट को वापस लेने के फैसले को चुनौती नहीं दे रहे थे, लेकिन बिना किसी पर्ची या पहचान पत्र के नोट बदलने पर रोक लगवाना उनका मकसद था।

उन्होंने जोर देकर कहा कि 2000 रुपये के बैंक नोट को बैंक खाते में जमा के माध्यम से बदलने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि नोट बदलने के लिए आईडी प्रूफ क्यों नहीं मांगा जा रहा है? हर गरीब का जनधन खाता है। बीपीएल व्यक्ति भी बैंक खातों से जुड़े हुए हैं। उपाध्याय ने दावा किया कि मौजूदा व्यवस्था से केवल अतीक अहमद के गुर्गे% जैसे माफिया, गैंगस्टर और नक्सली ही फायदा लेंगे।

आरबीआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पराग पी त्रिपाठी ने इस बात पर जोर दिया कि अदालत ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है और परिचालन सुविधा के लिए 2000 रुपये के नोट को बदलने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने कहा, यह नोटबंदी नहीं है। 2000 रुपये के बैंक नोट का आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता था। अन्य मूल्यवर्ग के नोट पर्याप्त मात्रा में परिचालन में मौजूद हैं।

उन्होंने कहा, यह एक वैधानिक कवायद है। याचिकाकर्ता की ओर से किए गए दावों में से कोई भी संवैधानिक मुद्दों के उल्लंघन से संबंधित नहीं है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।

प्रमुख समाचार

सचिन पायलट को दिल्ली में किया गया तलब

नई दिल्ली। पायलट बनाम गहलोत- कांग्रेस के बागी नेता सचिन पायलट को मंगलवार शाम को दिल्ली तलब किया गया है। राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर रंधावा को भी दिल्ली बुलाया गया है। खबरों की मानें तो दोनों नेता राजस्थान में चल रही आंतरिक कलह को लेकर पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर सकते हैं। सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच 2020 से सत्ता को लेकर खींचतान चल रही है। पायलट ने 11 मई को वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली पिछली भाजपा सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार और सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों को उठाने के लिए अजमेर से जयपुर तक 125 किलोमीटर की जन संघर्ष यात्रा शुरू की थी। समन के बाद पायलट ने अपना दौरा रद्द कर दिया और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उन्हें आज यात्रा को करौली तक आगे बढ़ाना था।

मंत्री एमबी पाटिल का दावा, पांच साल सीएम रहेंगे सिद्धारमैया

बेंगलुरू। कर्नाटक के मंत्री एमबी पाटिल ने सोमवार को कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके डिप्टी डीके शिवकुमार के बीच कोई सत्ता-साझाकरण समझौता नहीं है। दोनों ने शनिवार को शीर्ष पद पर लंबे समय तक गतिरोध के बाद शपथ ली थी। पाटिल ने कहा कि सिद्धारमैया पांच साल के लिए सीएम रहेंगे। उन्होंने कहा कि सत्ता की साझेदारी का समझौता होता तो वरिष्ठ नेता सूचित करते। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अगर ऐसा कोई प्रस्ताव होता तो केसी वेणुगोपाल या एआईसीसी के महासचिव सूचित करते। इसी को डीके शिवकुमार ने कहा कि कोई कुछ भी कहे। मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा। एआईसीसी सत्ता और पार्टी के अन्य मुद्दों को देखने के लिए है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता केवल राज्य का सर्वांगीण विकास है। आपको बता दें कि इस बात की चर्चा थी कि सिद्धारमैया और शिवकुमार में से प्रत्येक के पांच साल के कार्यकाल के 2.5 साल की सेवा करने की बात हुई थी।

केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ ताजा समन जारी

नई दिल्ली। गुजरात की एक अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि के मामले में 7 जून को पेश होने के लिए एक नया समन जारी किया है। याचिकाकर्ता के वकील अमित नायक ने बताया कि कोर्ट ने 15 अप्रैल को दोनों आरोपियों (अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह) को कोर्ट में पेश होने को कहा था। आज उसी के सिलसिले में तारीख थी लेकिन समन में ज्यादा स्पष्टता नहीं है इसलिए न्यायाधीश ने आदेश दिया है कि दोनों आरोपियों को शिकायत प्रतियों के साथ नए सिरे से समन जारी किया जाए। सुनवाई की अगली तारीख 7 जून है।

मंदिरों में अब नहीं लगेंगी आरएसएस की शाखाएं

कोच्चि। त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड ने अपने नियंत्रण वाले सभी मंदिरों को निर्देश जारी किया है कि वे मंदिर परिसर में आरएसएस द्वारा आयोजित सामूहिक अभ्यास और अन्य गतिविधियों की अनुमति न दें। हालांकि इस संबंध में एक प्रतिबंध पहले से ही लागू है, नया निर्देश राज्य भर के कुछ मंदिरों में अभी भी आरएसएस की गतिविधियों के जारी रहने की खबरों के मद्देनजर आया है। त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड अध्यक्ष के अनंतगोपन ने कहा कि आरएसएस की शाखाएं कई मंदिरों में चल रही थीं और वहां अभ्यास कर रही थीं। यही वजह है कि ऐसा सर्कुलर जारी किया गया। मंदिर श्रद्धालुओं के लिए होते हैं, श्रद्धालुओं को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। यह है बोर्ड का स्टैंड है। त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड ने 18 मई को एक सर्कुलर जारी कर उनके अधीन सभी मंदिरों को मंदिर परिसर में आरएसएस द्वारा आयोजित सामूहिक अभ्यास और अन्य गतिविधियों की अनुमति नहीं देने के लिए कहा।

ऑस्ट्रेलियाई शहर को मिला पहला भारतीय मूल का लॉर्ड मेयर

सिडनी। सिडनी में सिटी ऑफ पररामट्टा काउंसिल ने सोमवार (स्थानीय समय) पर भारतीय मूल के पार्षद समीर पांडे को अपना नया लॉर्ड मेयर चुना। समीर पांडे का पद के लिए चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीस के निमंत्रण पर दो दिवसीय यात्रा के लिए सोमवार को सिडनी पहुंचने के साथ हुआ। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि समीर पांडे पहली बार 2017 में परिषद के लिए चुने गए थे और 2022 में भारतीय उपमहाद्वीप से शहर के पहले डिप्टी लॉर्ड मेयर बने। बिहार से ऑस्ट्रेलिया आए समीर पांडे पहली बार 2017 में परिषद के लिए चुने गए थे। 2022 में वह भारतीय उपमहाद्वीप से परमट्टा के पहले डिप्टी लॉर्ड मेयर बने। वड्डु पार्षद डोना डेविस एमपी की जगह लेंगे, जिन्होंने परामत्ता के लिए राज्य सदस्य के रूप में उनके चुनाव के बाद अपनी भूमिका से इस्तीफा दे दिया था। समीर पैरामैटा के लॉर्ड मेयर के रूप में काम करेंगे।

कर्नाटक में कांग्रेस की जीत ने विपक्षी एकता को दी नई ताकत

राजेश बादल

■ **भ्रम में डूबे क्षेत्रीय और प्रादेशिक दलों के लिए भी सोचने का नया अवसर**

सियासी मंच पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों ने कुछ नए समीकरणों का संकेत दिया है. चुनाव से पहले क्षेत्रीय और प्रादेशिक दल कुछ ठिठके से और भ्रम में डूबे दिखाई दे रहे थे. लेकिन कांग्रेस की जीत ने उन्हें नए सिरे से सोचने का अवसर दिया है. कर्नाटक में निर्वाचन से पहले गैरभाजपा और गैरकांग्रेस वाले गठबंधन की तरफ इन दलों ने कुछ कदम बढ़ाए थे. तीसरे मोर्चे की ओर वे दो कदम आगे और एक कदम पीछे वाले अंदाज में चल रहे थे. पर बदले राजनीतिक परिदृश्य में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते नजर आ रहे हैं कि देश की सर्वाधिक बुजुर्ग पार्टी के बिना विपक्षी एकता संभव नहीं है.

अलबत्ता अपने प्रादेशिक हितों के चलते ऐसे गठबंधन से दूर रहना कुछ पार्टियों की विवशता भी है. दूसरी ओर कांग्रेस के नजरिये से बीता पखवाड़ा इसलिए भी लाभदायक रहा है कि क्षेत्रीय पार्टियां अब यूपीए के अस्तित्व को चुनौती नहीं दे सकेंगी. आपको याद होगा कि बीते दिनों राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार की उपस्थिति में तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा था कि यूपीए का कोई अस्तित्व ही नहीं है और न ही कांग्रेस उसकी अगुआई कर रही है. हालांकि सियासी गलियारों में उनके इस कथन को अधिक महत्व नहीं दिया गया क्योंकि एक-डेढ़ करोड़ मतदाताओं के वोट बैंक वाली पार्टी बारह-तेरह करोड़ मतदाताओं का जनाधार रखने वाली पार्टी के अस्तित्व को नकारे- यह मासूमियत भरा ख्याल ही है.

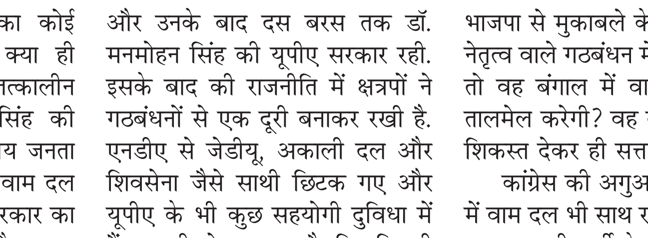

वैसे तो करीब-करीब हर आम चुनाव से पहले विपक्षी एकता और तीसरे मोर्चे की कवायद होने लगती है. कई दशकों से हम यह अनुभव देख रहे हैं. मगर वह शायद ही कभी परवान चढ़ी हो. अपवाद के तौर पर 1977 का आम चुनाव याद कर सकते हैं. लेकिन उस दौर की परिस्थितियां तथा राजनीतिक समीकरण एकदम अलग थे. कांग्रेस को पराजित करने के मकसद से जो गठबंधन जनता पार्टी की शक्ल में सामने आया, वह तीन साल के भीतर ही बिखर गया.

इसके बाद 1989 में भी कुछ पार्टियों के गठजोड़ हुए थे, पर वे नाकाम रहे. वे सिर्फ कांग्रेस को हराने के लिए बने थे और उनका कोई वैचारिक आधार नहीं था. क्या ही दिलचस्प नजारा था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की जनता दल सरकार को भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे रही थी और वाम दल भी साथ में थे इसलिए उस सरकार का अंजाम भी विनाशकारी रहा और 1991 के चुनाव में गठबंधन बिखरा हुआ था. बाकी कुछ अवसरों पर छोटे दलों ने बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों से समझौते किए, मगर उनका आधार वैचारिक नहीं था. उसके पीछे छोटी पार्टियों के अपने स्वार्थ थे.

अलबत्ता 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के कौशल की वजह से एनडीए ने पूरे पांच साल सरकार चलाई और उनके बाद दस बरस तक डॉ. मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार रही. इसके बाद की राजनीति में क्षत्रपों ने गठबंधनों से एक दूरी बनाकर रखी है. एनडीए से जेडीयू, अकाली दल और शिवसेना जैसे साथी छिटक गए और यूपीए के भी कुछ सहयोगी दुविधा में हैं.यह भी देखा गया है कि विपक्षी गठबंधन के लिए जो दल शुरुआत में साथ आते हैं, वे आपसी मतभेद और हितों के टकराव के कारण बाद में दम तोड़ देते हैं. वजह यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो दल विपक्ष की एकता के लिए प्रयास करते दिखाई देते हैं, प्रादेशिक स्तर पर वे स्थानीय समीकरणों के कारण टूट जाते हैं. एक-दो उदाहरण ही प्रासंगिक होंगे. यदि तृणमूल कांग्रेस भाजपा से मुकाबले के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हो जाए तो वह बंगाल में वाम दलों से कैसे तालमेल करेगी? वह तो वाम मोर्चे को शिकस्त देकर ही सत्ता में आई थी.

कांग्रेस की अगुआई वाले गठबंधन में वाम दल भी साथ रहेंगे ही. इसी तरह आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस कैसे सहज महसूस कर सकती है, जिसने उसके दिल्ली और पंजाब के मजबूत किलों को ध्वस्त किया हो. यह विचित्र सी बात होगी कि कोई पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को हराने के लिए तो कांग्रेस के साथ आ जाए, लेकिन प्रदेश स्तर पर वह उसी कांग्रेस के खिलाफ लड़े. वह अपना जनाधार घटाकर कांग्रेस के साथ चुनावी तालमेल क्यों करना चाहेगी।

गोठान घोटाला आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से अब तक का सबसे बड़ा घोटाला : राजीव

■ गोबर खरीद, खाद निर्माण मे हो रहा भारी भ्रष्टाचार - अरविंदर मुंडी

धमतरी। चलबो गोठान खोलबो पोल अभियान के अंतर्गत भाजपा के सभी बड़े नेता इस भीषण गर्मी मे इन दिनों गोठानों का निरीक्षण वहाँ की दुर्दशा को जनता के बीच लाने का काम कर रहे हैं । शनिवार को धमतरी विधानसभा के ग्राम कोलियारी, करेठा से लेकर ढीमर टुकुर तक 10 से अधिक गोठानों के दौरे पर गये भाजपा के धमतरी विधानसभा के प्रभारी राजीव पांडेय एवं सिहावा की पूर्व विधायक पिंकी शिवराज शाह के साथ जिले एवं मंडल के पदाधिकारियों ने गोठान की दशा पर आक्रोश एवं दुख व्यक्त किया ।

पूर्व विधायक पिंकी शिवराज शाह ने कहा कि अपने आपको किसान पुत्र बताने वाले छ्ग के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी के नाम से लोक लुभावन योजना जब प्रदेश मे शुरू की तो ग्रामीणों को ये लगा कि अपने ही बीच का माटीपुत्र किसान का बेटा प्रदेश का राजपाट संभाल रहा है । गाँव गाँव मे गोठान बना कर आम जनता को बड़े बड़े सपने दिखाये । सरकार अब अपने कार्यकाल के अंतिम चरण मे है, राज्य की जनता पग पग पर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है ।

मनरेगा, डीएमएफ फंड तथा केंद्र सरकार के 14 वें एवं 15 वें वित्त की राशि जिसका उपयोग गाँवों मे मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए किया जाता है उन पैसों मे से करोड़ों रुपये का दुरूपयोग जबरन मद परिवर्तन कर गोठानों मे किया गया जिसके चलते गाँवों मे विकास के सारे कार्य रुक गये हैं । प्रत्येक गोठानों मे लगाए गये लाखों रुपयों का न तो जनहित मे कोई उपयोग हो

रहा न ही गौमाता की कहीं कोई सेवा हो रही। सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया । विधानसभा प्रभारी राजीव पांडेय ने बताया कि सारे गोठान खाली पड़े हैं । गोठानों मे जहाँ 300 गायों को रखने का नियम है वहाँ गाय का नामो निशान तक देखने को नही मिलता जबकि सड़कों पर गौमाता को मरने के लिये छोड़ दिया जाता है । उनके चारा का पैसा, उनके रखरखाव के नाम से निकलने वाला प्रति गोठान प्रति माह 10 हजार रुपया बीच के दलालों की जेब मे जा रहा है । छत्तीसगढ़ का गोठान घोटाला आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है।

जिला उपाध्यक्ष अरविंदर मुंडी, मंडल अध्यक्ष हेमंत चंद्राकर ने गोठानों मे गोबर खरीदी और खाद के निर्माण के काम की पोल खोलते हुए बताया कि गोठानों के लिए बनाई गयी समिति अदृश्य समिति है इनके सदस्यों को कभी किसी ने गोठान पर देखा नही है । हफ्ते या महीने मे 1-2 दिन भी गोबर खरीदी नही की जाती । बहुत से गोठानों पर तो कागजों मे ही गोबर खरीदी हो जाती है और भुगतान किसकी जेब मे जाता है उसका भी कोई अतापता नही होता । कंपोस्ट खाद का निर्माण और उसको खपाने मे लगी सरकारी मशीनरी का अपना एक अलग सिंडिकेट चल रहा है । आधे से अधिक मिट्टी और मुरुम मिले खाद किसानों को जबरन 300 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से सरकार दबाव पूर्वक बेच रही है । 10 रुपये किलो मे बिकने वाले खाद मे से केवल 3 रुपये पूरी मेहनत करने वाली स्व सहायता समूह की महिलाओं को मिलता शेष बचे 7 रुपये का बंदरबांट हो जाता है । गोठान गौसेवा का स्थान नही बल्कि भ्रष्टाचार की स्थली बन गये हैं । गाँव के गरीब किसान खुद को बुरी तरह ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं । इस कार्यक्रम मे नेताओं के साथ मिश्री पटेल, प्रीतम साहू, दयाराम साहू, निरंजन साहू, आनंदस्वरूप मेश्राम, राजेंद्र साहेब, दयाराम सिन्हा, गोपाल साहू, गजेंद्र साहू, मधु, गीतेश्वरी, अमरीका बाई, लोकनाथ, सुभाष साहू, नरेश साहू, चेतन यदु, रामकुमार यादव, धन्नू जांगड़े, मनोहर सोनकर, अग्निवंशी सहित स्थानीय निवासी बड़ी संख्या मे सम्मिलित हुए ।

जबर्रा के गौठान में भ्रष्टाचार की हदें पार: दिनेश्वरी नेताम

नगरी। चलबो गौठान-खोलबो पोल के तहत 22 मई सोमवार सुबह 9.30 बजे भारतीय जनता पार्टी मंडल नगरी के जबर्रा के गौठान में दिनेश्वरी नेताम अध्यक्ष जनपद पंचायत नगरी ने अजजा मोर्चा जिला धमतरी जिलाध्यक्ष महेन्द्र नेताम, स्थानीय प्रभारी रामजी यादव और पूरन ध्रुव के साथ निरीक्षण किया।

वास्तव में जबर्रा के गौठान में भ्रष्टाचार की हदें पार हो गई है। गौठान में न घेरा है, न मवेशियों के लिए चारा की व्यवस्था है और न ही पानी कोटना में पानी भरने के लिए पाईप लाईन है।

14वें वित्त की राशि जो गांव के विकास के लिए लगना चाहिए उसे गौठान के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया है। सरपंच और वार्ड पंचों को भी नहीं पता कि 14वें वित्त की राशि गौठान में लगा है।

वर्मी टांका, गोबर टांका बनाने में भी भ्रष्टाचार किया गया है। टांका बना कर खुला छोड़ दिया गया है, जर्जर है।

लगभग 400 मवेशियों के हिसाब से गौठान बना है पर सबका कहना है कि यहां मवेशी नहीं आते। महिला समूह की बहनों ने बताया कि गोबर खरीदी बहुत पहले से बंद है। बिना मांग किये कचरा घर और मुर्गी शेड बनाया जा रहा है जो कोई काम का नहीं।

दस हजार रूपए हर माह आता है कि नहीं गौठान अध्यक्ष को भी नहीं पता। ग्रामीणों ने बताया कि गोठान में स्वीकृत राशि के हिसाब से काम नहीं हुआ है। सरपंच का भी कहना है कि पंचायतों में काम जीपीडीपी के हिसाब न होकर थोपा हुआ काम होता है।

जनता का पंचनामा में मानिकराम, अनिरूद्ध ध्रुव, रामजी यादव, सरपंच दशरथ नेताम, राजकुमार, ललित नारायण, पूरनलाल ध्रुव, रविकुमार एवं समूह की कुछ महिलाएं आदि शामिल रहे।

मुंगेली में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने चलबो गोठान खोलबो पोल के तहत गौठान का किया निरीक्षण

मुंगेली। विधानसभा मुंगेली के ग्राम भटगांव,बछेरा,बमुरहा में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद अरुण साव ने भाजपा संगठन के महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान के तहत गौठान का निरीक्षण भाजपा कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में किया।

ग्राम भटगांव में ग्रामीणों के साथ गौठान का निरीक्षण कर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने बताया कि जिस आदर्श गौठान को आप और हम देखने आये हैं, इसमें लाखों रुपए आहरण कर खर्च किया गया परंतु गौठान में दरवाजा ही नहीं है,फेंसिंग टूटा हुआ है, अंदर एक भी गाय नहीं है,पानी का टांका टूटा हुआ है, वर्मी कम्पोस्ट टांका में गोबर के बजाए सुखी हुई मिट्टी मिली,बकरी शेड में बकरी नहीं है, मुर्गी शेड में मुर्गी एक भी बार नहीं रखा गया है। सड़ा हुआ पैरा जिसके बारे में ग्रामीणों ने बताया कि इसे आज ही प्रदेश अध्यक्ष व सांसद के दौरे के मद्देनजर लाकर रखा गया है। इन सब कारण से ये प्रतीत होता है कि भूपेश बघेल सरकार ने गोठान के नाम से घोटाला करने के उद्देश्य से गोठान का निर्माण किया है। इसके पश्चात ग्राम बमुरहा के गौठान में न तो तार घेरा किया गया है न ही गाय रखा जाता है जबकि गौठान में गाय रखने का नियम हैं और वहां एक भी गाय नही है ,गौठान में गोबर खरीदी नहीं होती है, न ही कम्पोस्ट खाद बनाया जा रहा है। टांका में मिट्टी भरा हुआ है। गौठान का निरीक्षण करने में ये भी पाया गया कि गौठान में एक भी पैरा नहीं है। ग्राम बछेरा के गौठान का भी निरीक्षण सांसद अरुण साव ने किया। ग्रामीणों ने गौठान निर्माण की लागत लगभग 20 लाख का बताया. लेकिन चलबो-गौठान, खोलबो पोल अभियान के तहत निरीक्षण करने से भूपेश बघेल सरकार सारी पोल खुल गई। गौठान में पूरी तरह अव्यवस्थता देखने को मिला. भ्रष्टाचार की सारे हदें पार कर दी गई है। चलबो-गौठान, खोलबो-पोल अभियान के तहत निरीक्षण के दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने ग्रामीण जनता के समक्ष भूपेश बघेल सरकार के घोटालों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन ग्रामीण महामंत्री नितेश भारद्वाज ने किया। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष शैलेश पाठक,विनय पाण्डेय,दीनानाथ केशरवानी, जिला पंचायत सदस्य शीलू साहू,दुर्गा उमाशंकर साहू,जनपद उपाध्यक्ष पवन पाण्डेय, नगर पालिका उपाध्यक्ष मोहन मल्लाह,नगर मण्डल अध्यक्ष राणाप्रताप सिंह,ग्रामीण मण्डल अध्यक्ष शंकर सिंह,सुनील पाठक, संजय वर्मा,आशीष मिश्रा,शैलेंद्र तिवारी, मिट्ठूलाल यादव, प्रदीप पाण्डेय, कोटूमल दादवानी, उमाशंकर साहू,नंदू सिंह,मोहित बंजारा,राजीव श्रीवास,अमितेषआर्य, आलोक,यश गुप्ता,करन सिंह,अरविंद सिंह,सचिन मसीह,मेलाराम साहू,प्रमोद रावलानी विस्तारक यश शुक्ला,सरपंच माधो साहू,उपसरपंच सुखूराम साहू,सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता व ग्रामीण जन उपस्थित रहे।

भाजपा गोठानों को बदनाम करने अभियान चला रही है: कांग्रेस

धमतरी। जिला कांग्रेस कमेटी ने कहा कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार देश की अकेली सरकार है जो गौसेवा के लिये गांव के गोधन एवं अन्य पशुओं के लिये गोठान बना कर गोसेवा कर रही है तो भाजपा को इसमें भी पीड़ा हो रही।

धमतरी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शरद लोहाना छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष मोहन लालवानी ने कहा कि भाजपा गोठानों को बदनाम करने के लिये अभियान चला रही जबकि गोठानों और गोधन न्याय योजना की तारीफ पूरे देश में हो रही। भाजपा गोठानों में भ्रष्टाचार की बात कर अपनी खीझ निकाल रही है। भाजपा को गोठान और गौशाला के बीच का मूल फर्क ही नहीं मालूम। गोठान छत्तीसगढ़ की वर्षों की पुरातन परंपरा है, हमारी सरकार ने गांवों के उसी गोठान को संवारने का काम किया है। उन्होंने ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में गांव, गरीब, किसानों और गोपालको की

समृद्धि को भाजपाई पचा नहीं पा रहे हैं। गरीब और कृषि श्रमिको सहित ग्रामीणों के अतिरिक्त आमदनी का जरिया बने गोधन न्याय योजना का विरोध कर भाजपाई अपने सामंतवादी चरित्र को एक बार फिर प्रमाणित कर रहे हैं।

भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में विगत साढ़े तीन साल में 10624 गोठान बनाए हैं जिनमें से 5709 गोठान अब स्वावलंबी बन चुके हैं। योजना के अंतर्गत कोई भी राशि का भुगतान नगद रूप में नहीं होता है। प्रत्येक 15 दिन में हितग्राहियों के बैंक खाते में राशि का अंतरण होता है, पूरी पारदर्शिता है।

उन्होंने ने कहा कि 15 साल रमन राज के कुशासन में आरएसएस, भाजपा नेताओ के द्वारा संचालित फर्जी गौशालाओं को हर साल करोड़ों का अनुदान लगातार दिया जाता था, जहां अनुदान गटक कर चारा-पानी के बिना गाएं मार दी जाती। उन्होंने ने कहा कि प्रदेश में संचालित गोठानों में 14504 महिला स्व सहायता समूह की 1,71,585 बहनों को 131 करोड़ 43 लाख का भुगतान अब तक हो चुका है। यही नहीं गोपालकों और समूहों को अब तक 445 करोड़ 14 लाख का भुगतान, 21 मई 2023 को 13 करोड़ 57 लाख दिए जाएंगे। प्रदेश में पंजीकृत गोपालकों की संख्या 341713 है, चुका है। करोड़ का प्रावधान किया गया है।

पूर्व विधायक श्रवण मरकाम ने भाजपाइयों संग कुकरेल क्षेत्र के गौठानों का निरीक्षण किया

नगरी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आव्हान पर भाजपा मंडल कुकरेल के द्वारा भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार के गोधन न्याय योजना गौठान में हुए 1300 करोड़ रूपये के भ्रष्टाचार को उजागर करने चलबो गौठान-खोलबो पोल अभियान के अन्तर्गत गाँव-गाँव के गौठान में पहुँच कर लोगों को भूपेश सरकार के नकामियो को बता रहे हैं। वही केन्द्र सरकार के द्वारा मनरेगा,स्वच्छ भारत,14 वां वित्त, 15 वां वित्त,डी.एम.एफ जैसे योजनाओं से पंचायत व गाँव के विकास के लिए राशि भेजी जाती है उसे भी गौठान के नाम पर भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार भारी भ्रष्टाचार कर रही है। जिससे गाँव के साथ अन्याय हो रहा है। भूपेश सरकार रोका-छेका की बात करतीं हैं लेकिन गाय सड़क पर नजर आती है।आज भाजपाईयों ने ग्राम छुही,, कुकरेल,, सलोनी,, माकरदोना,, बनबगौद के गौठान में पहुँच कर हल्ला बोला।

चलबो गौठान-खोलबो पोल अभियान कार्यक्रम में पूर्व विधायक सिहावा श्रवण मरकाम, मंडल अध्यक्ष वामन साहू, जिला पंचायत सदस्य अनीता ध्रुव, सरपंच महेश गोटा, महामंत्री अजय यादव,उपाध्यक्ष चन्द्रकला साहू, कोषाध्यक्ष मोहन दास मानिकपुरी, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष शैलेन्द्र साहू, महामंत्री अजय ध्रुव, भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष शुभम यदु, सरपंच नरेश दीवान, सियाराम साहू, मोहित निषाद, टिकेश्वर साहू, शत्रुहन साहू, हेमलाल साहू, लक्ष्मी कांत साहू, सत्तु राम साहू, केश कुमार साहू, श्रीमती केशर बाई साहू, सरोज बाई साहू उपस्थित रहें।

छत्तीसगढ़
प्रमुख समाचार

9 पार्षद और जनपद उपाध्यक्ष का भाजपा से निलंबन समाप्त

महासमुंद। भाजपा के 9 पार्षद और एक जनपद उपाध्यक्ष का पार्टी से निलंबन अब समाप्त हो गया है। इस आशय का आदेश प्रदेश महामंत्री व मुख्यालय प्रभारी केदार कश्यप ने जारी किया। जारी सूची में कुल 10 लोगों में से 8 महासमुंद नगर पालिका के पार्षद और एक सरायपाली नगर पालिका के पार्षद, एक बागबाहरा जनपद उपाध्यक्ष शामिल हैं। मालूम हो कि इन पार्षदों और जनपद उपाध्यक्ष को पार्टी विरोधी गतिविधि के कारण भारतीय जनता पार्टी से निलंबित किया गया था। इन्हें अब फिर से पार्टी में शामिल कर लिया गया है। निलंबन के बाद पार्टी में वापस आने वाले सदस्यों में नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष पवन पटेल, पार्षद महेन्द्र जैन, पार्षद मीना वर्मा, पार्षद मंगेश टांकसाले, पार्षद मनीश शर्मा, पार्षद मोहम्मद हफीज खान, पार्षद मुन्ना देवार, पार्षद माधवी सिका, राखी गणेश चौहान, भेखलाल साहू शामिल हैं।

राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया

खरोरा। धरसींवा विधानसभा अंतर्गत धरसींवा ब्लॉक मुख्यालय शहीद स्मारक में धर्म निरपेक्ष भारत के सशक्त पक्षधर और आधुनिक भारत के निर्माता, भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री स्व राजीव गांधी के पुण्यतिथि में आतंक वाद विरोध दिवस के रूप में माल्यार्पण एवं श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। जिसमें मुख्य रूप से विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा उपस्थित रही। कांग्रेस सरकार के द्वारा राजीव गाँधी के सहादत दिवस में किसान न्याय योजना में 24.52 लाख किसानों के खाते में 1894.93 करोड़ रु की आदान सहायता अब 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर नया योजना 5.63 लाख हितग्राहियों को 112.71 करोड़ रु का भुगतान लाभार्थियों को 7,000 रु सालाना आर्थिक सहायता, गोधन न्याय योजना पशु पालकों, गौठान समितियों व स्व-सहायता समूहों को 13.57 करोड़ रु प्रदत्त, राजीव युवा मितान क्लब 13 जिलों के 3.085 क्लबों को 7.71 करोड़ रु का वितरण युवाओं की प्रतिभा को प्रोत्साहन प्रदत्त किया गया।

एनएसएस समर केम्प में दोना पत्तल तैयार किया जा रहा

चांपा। समर वोकेशनल का लाभ उठाते हुए तथा देशी प्राकृतिक संसाधनों से तथा पर्यावरण संरक्षण करते हुए साजा, साल, सरई के पत्ते से दोना पत्तल तैयार कर प्लास्टिक, पालीथीन से बने कटोरी थाली के स्वास्थ्य गत दुष्प्रभाव से बचने वअधिक आर्थिक व्यय से बचाने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई कोथारी के कार्यक्रम अधिकारी धरम लहरे के मार्गदर्शन में एवं सहयोग से स्वयंसेवकों व ग्रामीण महिलाओं के सौजन्य से ग्राम गितारी में दोना पत्तल तैयार किया जा रहा है जिसे स्वयं सेवकों द्वारा कम कीमत में जरूरत मंद व्यक्तियों एवं परिवारों को उपलब्ध कराया जा रहा है ग्रीष्मकालीन अवकाश का सदुपयोग भी हो रहा है और उपयोग में लाये गये दोना पत्तल को नष्ट कर या सड़ाकर खाद के रूप में गार्डन में उपयोग किया जा सकता है । इसके उपयोग से अनावश्यक अधिक दाम में मिलने वाले प्लास्टिक के थाली कटोरी से आर्थिक बचत भी हो रही है। साथ ही स्वयंसेवक इन सामग्रियों को बेचकर अपनी आवश्यकता की वस्तुएं पुस्तक, कपड़े, तथा खाने की ऐच्छिक वस्तुएं आसानी से खरीद रहें हैं।

नेशनल म्युथाई बाक्सिंग चैंपियनशिप के लिए 61 खिलाड़ियों का चयन

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के 61 खिलाड़ियों का चयन नेशनल म्युथाई बाक्सिंग चैंपियनशिप के लिए किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा बस्तर के खिलाड़ी शामिल हैं। अकेले बस्तर से 28 खिलाड़ी हैं। जबकि रायपुर से रायपुर से 16, बालोद से नौ और कोरबा से आठ खिलाड़ियों को चुना गया है। यूनाइटेड म्यू थाई एसोसिएशन इंडिया की ओर से चेन्नई में इस प्रतियोगिता का आयोजन 25 से 30 मई के बीच किया जा रहा है। इस दौरान राष्ट्रीय म्यू थाई चैंपियनशिप और प्रो नाईट फाइट होगी। प्रतियोगिता सीनियर, जूनियर, सब जूनियर (बालक-बालिका) वर्ग में होगी। प्रतियोगिता में बस्तर जिले से 9 बालिका और 19 बालक का चयन किया गया है। यह टीम कोच अब्दुल मोईन, नवीन ठाकुर महिला कोच, मकसुदा हुसैन, सुमन राव व मैनेजर राजेन्द्र राजपूत, कृष्ण कुमार यादव के नेतृत्व में भाग लेने के लिए रवाना होगी। बस्तर के खिलाड़ी 24 मई को दोपहर 12 बजे न्यू बस स्टैंड से चेन्नई के लिए रवाना होंगे।

मरवाही के जंगल धधके कई पेड़-पौधे जले

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का असर दिखना शुरू हो गया है। इसके चलते जंगल भी आग की चपेट में आ गए हैं। जशपुर और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के जंगल धधक रहे हैं। इसके कारण पेड़-पौधों के साथ ही औषधीय पौधे भी जल गए हैं। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम आग बुझाने के प्रयास में जुटी हुई है। हालांकि तेज हवाओं के चलते आग बढ़ती जा रही है और टीम को उसे बुझाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जशपुर में तो जंगल में आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के मरवाही वन मंडल के खोडरी वन परिक्षेत्र के जंगलों में भीषण आग लगी है। इसके चलते बस्ती बगरा इलाके के जंगलों का बड़ा इलाका चपेट में है। जंगल में लगी आग की सूचना ग्रामीणों से मिलने के बाद वन प्रबंधन समिति के कर्मचारी आग बुझाने के प्रयासों में जुट गए हैं। दो कर्मचारी एक ग्रोवर मशीन लेकर आग बुझाने पहुंचे हैं। कम संसाधन होने की वजह से आग को काबू करने में काफी परेशानी हो रही है।

अकलतरा स्टेशन पर सुविधाओं के लिए प्रदर्शन, पुलिस से झड़प

जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा में अकलतरा रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं बढ़ाने की मांग को लेकर रेल संघर्ष समिति मंगलवार को प्रदर्शन रही है। नगर बंद कराकर बड़ी संख्या में लोग रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रहे थे। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई। प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। फिलहाल अकलतरा रेलवे स्टेशन को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है।

रेल संघर्ष समिति की ओर से रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा बढ़ने को लेकर बीच-बीच में धरना प्रदर्शन किया जाता रहा है। कई बार ज्ञापन देने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो समिति के बैनर तले नगर बंद करा दिया गया। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग स्टेशन का घेराव करने के लिए निकल पड़े। इसमें नगर के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल थे। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने स्टेशन से 50 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग कर दी थी।

प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तक पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रुकने के लिए कहा। लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं

माने और ऊपर चढ़कर आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे। इस पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। फिलहाल प्रदर्शन को देखते हुए 100 जवानों को तैनात किया गया है। वहीं रेलवे स्टेशन की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

रेल संघर्ष समिति की मांगे

ट्रेन नं-18113/18114 टाटा-बिलासपुर-टाटा एक्सप्रेस का अकलतरा में स्टापेज देना। ट्रेन नं. 12809 / 12810 मुम्बई मेल, ट्रेन नं. 12129 / 12130 आजाद हिन्द एक्सप्रेस एवं 12905 / 12906 हापा एक्सप्रेस का स्टापेज देना। प्लेटफार्म नं. 01 एवं 02 की दोनों दिशाओं की लम्बाई बढ़ाना। प्लेटफार्म नं. 01 एवं 04 पर कोच गाईडेंस डिसप्ले बोर्ड लगाना। सुलभ शौचालय को उपयोग के लिए खोलना। लिफ्ट को प्लेटफार्म नं. 03 एवं 04 पर भी लगाना। कोचिवेलू पेसेंजर स्पेशल को कोरबा-बिलासपुर- कोरबा के बीच खोलकर चलाना ।अंडरब्रिज का निर्माण करना।

गरीब रथ ट्रेन में लगी आग

रायपुर। गर्मी के सीजन में लगातार आग लगने की खबरें सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में फिर आग लगी है। रायपुर रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन में आग लग गई है। गनीमत रही कि रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में कर लिया। बताया जाता है कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 6 पर दुर्ग-लखनऊ गरीब रथ एक्सप्रेस खड़ी थी। शार्टसर्किट होने की वजह से बोगी में आग लग गई। ट्रेन केबोगी नंबर जी-4 में शार्टसर्किट से आग लग गई। सूचना पर रेलवे के अधिकारी तुरंत बोगी के पास पहुंचे।

पानी की तलाश में बस्ती में घुसे दो चीतल कुत्तों ने दौड़ाया तो कुएं में गिरा एक

अंबिकापुर। मंगलवार की सुबह दो चीतल पिलखा पहाड़ से नीचे उतर रेलवे स्टेशन के पास अजिरमा बस्ती में प्रवेश कर गए। कुत्तों की नजर पड़ी तो उन्होंने चीतलों को दौड़ाना शुरू किया। कुत्तों के डर से एक चीतल तो उछलकूद करते सुरक्षित भाग निकला लेकिन एक वयस्क चीतल रेलवे स्टेशन के सामने सोनसाय नामक व्यक्ति के खुले कुएं में गिर गया। इससे वह चोटिल भी हुआ। लोगों ने चीतल को कुएं में गिरते देखा था। जब नजदीक पहुंचे तो पता चला कि कच्चे कुएं में पानी कम है इसके बाद भी चीतल की छटपटाहट से उसकी जान भी जा सकती है।

इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। तत्काल वन विभाग को सूचना दी गई। वनकर्मियों के

पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि चीतल को कुएं से बाहर निकाला जा सके। एसडीआरएफ अंबिकापुर की टीम की मदद लेनी शुरू की गई। चीतल को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने एक सीढ़ी कुएं में लगाई। कुछ व्यक्ति नीचे उतरे। चीतल को सुरक्षित तरीके से पकड़ा गया। उसके सींग को रस्सी से बांधा गया ताकि कोई आपरेशन के दौरान सींग के वार से चोटिल न हो। फिर चीतल को पकड़ उसके पैर बांधे गए और सुरक्षित तरीके से ऊपर ले आया गया। इस पूरे घटना में चीतल बुरी तरह थक चुका था। कुत्तों से बचने तथा कुएं में गिरने से उसे चोट भी आई थी। वन कर्मचारियों ने ग्रामीणों की मदद से चीतल को पशु चिकित्सालय लाकर उसका प्राथमिक स्वास्थ्य जांच भी कराया। चीतल को कोई गंभीर चोट नहीं था लेकिन कुएं में निकलने के प्रयास में वह सुस्त पड़ गया था। उसे फिर से जंगल के नैसर्गिक वातावरण में छोड़ दिया जाएगा।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार

समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों को शरद पवार ने बताया सही

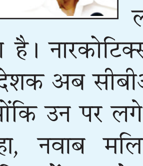

मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों को सही ठहराते हुए कहा कि हमारी पार्टी के नेता नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के खिलाफ जो कुछ भी आरोप लगाया है वह सच साबित हो रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व जोनल निदेशक अब सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं क्योंकि उन पर लगे आरोप सही है। शरद पवार ने कहा, नवाब मलिक को परेशान किया गया, मीडिया में सच बोलने की उन्हें कीमत चुकानी पड़ी थी। उस वक्त उन्होंने जो कहा था अब सच साबित हो रहा देखते हैं आगे क्या होता है। दरअसल, दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़े ईडी के एक मामले में नवाब मलिक 23 फरवरी, 2022 से जेल में है। इस मामले में नवाब मलिक पर जब कार्रवाई हुई तो उन्होंने मीडिया के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। इस मामले के कारण नवाब मलिक को महाराष्ट्र में अपना मंत्री पद तक गंवाना पड़ा था।

सिसोदिया की न्यायिक हिरासत एक जून तक बढ़ायी गई

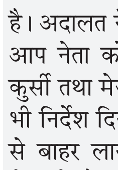

नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि एक जून तक बढ़ा दी है। अदालत ने मंगलवार को जेल प्राधिकारियों को आप नेता को जेल में किताबों के साथ ही एक कुर्सी तथा मेज उपलब्ध कराने पर विचार करने का भी निर्देश दिया। जब सिसोदिया को अदालत कक्ष से बाहर लाया जा रहा था, तो उन्होंने दिल्ली के सेवाओं के मामले पर केंद्र के अध्यादेश पर एक विधेयक लाए जाने के संदर्भ में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 'लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं।' दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, 'मोदी बहुत अहंकारी हो गए हैं।' दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को आबकारी नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 में यह नीति रद्द कर दी थी। सिसोदिया इस संबंध में सीबीआई तथा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मामलों में आरोपी हैं।

राजनीति को प्रभावित करता है 'सांप्रदायिकता का वायरस'

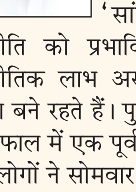

नयी दिल्ली। मणिपुर में सोमवार को हुई हिंसा की ताजा घटना पर राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने मंगलवार को कहा कि कोरोना वायरस केवल इंसान के शरीर को प्रभावित करता है, लेकिन 'सांप्रदायिकता का वायरस' राजनीति को प्रभावित करता है और इसके राजनीतिक लाभ अस्थाई होते हैं, लेकिन दाग हमेशा बने रहते हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इंफाल में एक पूर्व विधायक समेत हथियारबंद चार लोगों ने सोमवार को लोगों को अपनी दुकानें बंद करने के लिए बाध्य किया था, जिसके बाद राज्य में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी थी। इंफाल पूर्व जिले में भीड़ ने दो मकानों में आग लगा दी थी। सिब्बल ने ट्वीट किया, 'मणिपुर फिर से सुलग रहा है। पहले की झड़पों में 70 लोग मारे गए थे और 200 लोग घायल हुए थे। कोरोना वायरस केवल इंसान के शरीर को प्रभावित करता है, लेकिन 'सांप्रदायिकता का वायरस' राजनीति को प्रभावित करता है।'

कर्नाटक में हार पर मायावती ने जिम्मेदारों को लगायी फटकार

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने हाल में सम्पन्न कर्नाटक राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारियों को कैडर के आधार पर पार्टी का जनाधार बढ़ाने की हिदायत दी है। मायावती ने मंगलवार को यहाँ पार्टी के वरिष्ठ एवं जिम्मेदार पदाधिकारियों के साथ बैठक में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा की। इस दौरान बसपा प्रमुख ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार पर सख्त नाराजगी जतायी और कहा कि हर राज्य में पार्टी की तैयारी इस तरह से होनी चाहिए कि चुनाव में माहौल चाहे किसी भी पार्टी के पक्ष में हो मगर बसपा की स्थिति अच्छी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरफ खास ध्यान देने की जरूरत है। पार्टी द्वारा यहां जारी एक बयान के मुताबिक मायावती ने बैठक के दौरान कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी स्तर से रह गयी कमियों की तरफ ध्यान दिलाते हुए पदाधिकारियों से कैडर के आधार पर पार्टी के जनाधार को बढ़ाने की हिदायत दी।

पायलट के अल्टीमेटम पर सीएम खुद देंगे जवाब : रंधावा

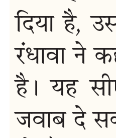

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत औ सचिन पायलट के बीच जारी खींचतान के बीच राजस्थान कांग्रेस के प्रमुख सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मंगलवार को कहा कि पायलट ने गहलोत को जो अल्टीमेटम दिया है, उसका जवाब देना गहलोत पर निर्भर है। रंधावा ने कहा, उन्होंने सीएम को अल्टीमेटम दिया है। यह सीएम ही हैं जो उनके अल्टीमेटम का जवाब दे सकते हैं। जब कांग्रेस पार्टी की बात होगी तो मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। राजस्थान कांग्रेस के प्रमुख सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा, वे [गहलोत-पायलट] राजस्थान में अकेले नेता नहीं हैं। और भी कई नेता हैं। मैं उन सभी से, सभी समुदायों के नेताओं से बात कर रहा हूं। पायलट ने गहलोत को धमकी दी है कि अगर महीने के अंत तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो वह राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। रंधावा ने कहा था कि कांग्रेस असंतुष्टों को बाहर नहीं करेगी, लेकिन याद दिलाया कि अतीत में नेताओं ने पार्टी छोड़ने के बाद कैसा प्रदर्शन किया था।

केंद्र के अध्यादेश पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं मिलेगा कांग्रेस का साथ

केजरीवाल अपनी लड़ाई को जनता की लड़ाई कैसे बना सकते हैं : माकन

नईदिल्ली। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल लगातार विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन मांग रहे हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि कांग्रेस की ओर से उन्हें समर्थन मिलने की उम्मीद बेहद कम है। दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने साफ तौर पर कहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार हमारी नेता शीला दीक्षित ने भी मांगा था। लेकिन उन्हें ना तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था और ना ही मनमोहन सिंह ने दिया था। इससे पहले मदन लाल खुराना ने मांगा था। उन्हें भी नहीं दी गई थी। तो फिर यह क्यों मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने मुख्यमंत्रियों को यह पावर नहीं दिया तो यह कौन से विलक्षण प्रतिभा वाले हैं कि इन्हें दे दिया जाए।

अजय माकन ने कहा कि वे (आप) अपनी लड़ाई को जनता की लड़ाई कैसे बना सकते हैं? वो कहते हैं शिक्षा में, स्वास्थ्य में बहुत काम किया है... ये जो श्रेय लेते हैं, ये भी दिल्ली में तैनात अफसरों का काम है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अफसर लाए क्या? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें डर है कि अब वे फंस गए हैं। वे लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। वे शराब घोटाले और अन्य घोटालों में फंस गए हैं। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस से समर्थन मांगने पर कांग्रेस नेता ने कहा कि वे कांग्रेस का समर्थन कैसे मांग रहे हैं? उन्होंने (अरविंद केजरीवाल) भाजपा के समर्थन से राजीव गांधी का भारत रत्न वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर भाजपा का समर्थन किया। उन्होंने जस्टिस दीपक मिश्रा के महाभियोग के दौरान बीजेपी का समर्थन किया था। एक व्यक्ति जो देश के बारे में नहीं सोचता, खालिस्तानी समर्थकों से बात करता है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का समर्थन करने के खिलाफ प्रशासनिक से लेकर कानूनी तक कारण बताए। हालांकि, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों केजरीवाल और कांग्रेस आलाकमान दोनों से मुलाकात की थी। तब इसको लेकर राय बनाने की कोशिश हुई थी। दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अपनी लड़ाई के लिए समर्थन जुटाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी दौरे के तहत, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार दोपहर कोलकाता में पश्चिम बंगाल की समकक्ष ममता बनर्जी से मुलाकात की। केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, "आज से देश भर में निकल रहा हूं। दिल्ली के लोगों के हक के लिए। उच्चतम न्यायालय ने बरसों बाद आदेश पारित करके दिल्ली के लोगों के साथ न्याय किया, उन्हें उनके हक दिये। केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर वो सारे हक वापस छीन लिये। जब ये क़ानून राज्य सभा में आएगा, तो इसे किसी हालत में पास नहीं होने देना। सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों से मिलकर उनका साथ मांगूंगा।"

तृणमूल कांग्रेस राज्यसभा में दिल्ली सेवाओं पर विधेयक का करेगी विरोध : ममता

कोलकोता। दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण को लेकर केंद्र के साथ चल रही खींचतान में आप को समर्थन देते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि तृणमूल कांग्रेस एनडीए सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश का विरोध करेगी और उन्होंने इस मुद्दे परे विपक्षी दलों से एक साथ आने का आग्रह किया। बनर्जी ने कोलकाता में बैठक के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके पंजाब समकक्ष भगवंत मान के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की। राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा और दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी भी मौजूद थीं।

यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब बनर्जी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गैर-भाजपा दलों का गठबंधन बनाने के लिए कई विपक्षी नेताओं के साथ बातचीत कर रही हैं। दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले, केजरीवाल ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के विपक्षी नेताओं से मिलेंगे कि जब अध्यादेश को बदलने के लिए एक विधेयक पेश हो, तो राज्यसभा में इसे पारित नहीं किया जाए।

इसी कड़ी में केजरीवाल बुधवार को मुंबई में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना (यूबीटी) के नेता उद्धव ठाकरे और 25 मई को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) सुप्रीमो शरद पवार से भी मुलाकात करेंगे। पिछले हफ्ते, केजरीवाल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण को लेकर केंद्र के साथ आप के चल रहे टकराव में जद (यू) नेता ने उन्हें पूरा समर्थन दिया।

राहुल-नीतीश की बैठक में तेजस्वी रहे नदारद, उठने लगे सवाल

पटना। विपक्षी एकता की मुहिम को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ दिल्ली का दौरा करने वाले उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से नही मिलने पर कयासों का बाजार गर्म हो गया है। हालांकि, तेजस्वी की अनुपस्थिती को अचानक तबीयत खराब हो जाना बताया गया। लेकिन क्या सिर्फ यही एक कारण है या कुछ और भी बात है, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्माता जा रहा है। जबकि इसके एक दिन पहले वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने गए हुए थे। तेजस्वी कांग्रेस के साथ हुई बैठक में क्यों नहीं गए? यह सवाल उठने लगा है।

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। तेजस्वी यादव, केजरीवाल से मिलने के लिए साथ गए, लेकिन राहुल गांधी से मिलने में बहाना बनाकर अलग हो गए। कहीं न कहीं मिलने में परेशानी थी। लग रहा था कि जिस तरह से बिहार में तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को परेशान किया है, औकात बताने का काम किया है। चाहे वह लोकसभा चुनाव हो या विधान सभा चुनाव हो या दूसरे मुद्दे। ऐसे में राहुल गांधी से आंख मिलाने में तेजस्वी यादव को परेशानी हो रही थी। इसलिए तेजस्वी यादव ने मिलने से इनकार कर गए। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने तो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी को भकचोन्हर तक कह दिया था। महागठबंधन में कांग्रेस को 70 सीटें विधान सभा चुनाव में दी गई थीं तब उन्होंने कहा कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस ठीक नहीं। यह दिखा था कि कमजोर सीट जबर्दस्ती कांग्रेस की झोली में डाला गया था। ऐसे में तेजस्वी यादव का कांग्रेस के साथ जाने में हिचकिचाहट या राहुल से मिलने में हिचकिचाहट जाहिर करता है कि कांग्रेस का नेतृत्व कई दल स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।

इस मीटिंग से यही अंदाजा लगाया जा सकता है। जानकारों की अगर मानें तो तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस के संबंध बेहतर नहीं हैं। विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव की नाराजगी कांग्रेस से इस

बात को लेकर रही कि कांग्रेस ने दबाव बनाकर 70 सीटें ले लीं और जीत पाई महज 19 सीट। इस वजह से तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बन पाई। हालांकि, खराब परफॉर्मेंस पर कांग्रेस के नेताओं का कहना रहा कि कमजोर सीटें पार्टी को दी गईं थीं। तेजस्वी का गुस्सा विधानसभा चुनाव के बाद हुए उपचुनावों में भी दिखा। बिहार में तारापुर, कुशेश्वर स्थान, बोचहां, गोपालगंज, कुढ़नी और मोकामा में उपचुनाव हुए। मोकामा, कुढ़नी और गोपालगंज के उपचुनाव नई सरकार बनने के बाद हुए। इसलिए कांग्रेस-राजद साथ थी, बाकी उपचुनावों में राजद ने कांग्रेस से बिना पूछे उम्मीदवार उतार दिए। महागठबंधन धर्म हवा में रहा। तब इस बात की चर्चा खूब थी कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का रुख क्या रहेगा?

नीतीश में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं और बिना लड़े मुख्यमंत्री बने

भाजपा में शामिल हुए पूर्व केन्द्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा तंज कसते हुए कहा है कि नीतीश कुमार में चुनाव लड़ने की गिम्मत नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश 2005 से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा और बिना चुनाव लड़े ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आरसीपी सिंह ने ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार की चुनौती पर यह जवाब दिया है। दरअसल, सोमवार को नालंदा में श्रवण कुमार ने कहा था कि नीतीश कुमार यहां से चुनाव लड़ते हैं तो रिकॉर्ड 3 लाख वोट से जीतेंगे। नालंदा से नीतीश के चुनाव लड़ने के सवाल पर आरसीपी ने कहा कि नालंदा में भाजपा को इतना मजबूत कर देंगे कि नीतीश चुनाव लड़ना तो दूर नालंदा की तरफ झांक भी नहीं पाएंगे।

खेल
प्रमुख समाचार

सुपरजाइंट्स के खिलाफ मुंबई का मुकाबला आज

चेन्नई। बल्लेबाजों की फॉर्म में वापसी की बदौलत प्ले ऑफ में जगह बनाने वाली मुंबई इंडियन्स की टीम बुधवार को यहां एलिमिनेटर में लखनऊ सुपरजाइंट्स के खिलाफ बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ उतरेगी। मुंबई की टीम पिछले इंडियन प्रीमियर लीग सत्र में अंतिम स्थान पर रही थी जिसके बाद मौजूदा सत्र में टीम ने वापसी करते हुए प्ले ऑफ में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस ने अंतिम लीग मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) को हराकर मुंबई की प्ले ऑफ में जगह सुनिश्चित की और रोहित शर्मा की अगुआई वाली टीम की नजरें अब अपने छठे आईपीएल खिताब पर टिकी हैं। सुपरजाइंट्स को पिछले सत्र में आरसीबी के खिलाफ एलिमिनेटर में ही हार का सामना करना पड़ा था और इस बार टीम इससे आगे बढ़ना चाहेगी। नियमित कप्तान लोकेश राहुल की गैरमौजूदगी के बावजूद टीम का संतुलन बरकरार है और कृणाल पंड्या ने उपलब्ध विकल्पों का काफी अच्छी तरह इस्तेमाल किया है और आईपीएल की सबसे सफल टीम के खिलाफ उन्हें लय बरकरार रखने की उम्मीद होगी। मुंबई के लिए अंतिम लीग मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने शानदार शतक जड़ा। सुपरजाइंट्स के खिलाफ बल्लेबाजी में टीम की नजरें सूर्यकुमार यादव (511 रन, एक शतक, चार अर्धशतक), सलामी बल्लेबाज इशान किशन (439), ग्रीन (381) और कप्तान रोहित (313) पर टिकी होंगी। मुंबई के बल्लेबाजों ने लय हासिल की है और ऐसे में सुपरजाइंट्स के गेंदबाजों की राह आसान नहीं होने वाली। सुपरजाइंट्स को अगर मुंबई के बल्लेबाजों को रोकना है तो लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को बड़ी भूमिका निभानी होगी जो 14 मैच में 16 विकेट के साथ टीम के सबसे सफल गेंदबाज हैं। नवीन उल हक, आवेश खान, कृणाल और अनुभवी अमित मिश्रा जैसे गेंदबाजों को भी अधिक योगदान देना होगा।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/ प्रमुख समाचार

सेंसेक्स में 18 अंक की मामूली तेजी

नईदिल्ली। घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में तेजी रही। उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में बीएसई सेंसेक्स मामूली 18 अंक की बढ़त में रहा। वैश्विक स्तर पर कमजोर रुख के बीच अमेरिकी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की बैठक का ब्योरा जारी होने से पहले निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया। कारोबार के अंतिम समय में उतार-चढ़ाव से तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स दिन के उच्चस्तर से नीचे आ गया और अंत में 18.11 अंक यानी 0.03 फीसदी की मामूली बढ़त के साथ 61,981.79 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 281.51 अंक तक चढ़ गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33.60 अंक यानी 0.18 फीसदी की तेजी के साथ 18,348 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में बजाज फिनसर्व, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स, इंडसइंड बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, टाटा स्टील, विप्रो और मारुति प्रमुख रूप से लाभ में रहे।

रिटेल कारोबार में बड़ा धमाका करने जा रहे मुकेश अंबानी

नई दिल्ली। भारत के दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी रिटेल कारोबार में बड़ा धमाका करने की तैयारी कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी ने चीन की कंपनी शीन के साथ लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया है। इस समझौते के तहत चीन की ऑनलाइन फास्ट फैशन रिटेलर कंपनी शीन अपनी टेक्निक शेयर करेगी। शीन कंपनी का समझौता मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के साथ हुआ है। इस समझौते के तहत चीन की यह कंपनी भारत में अपने कदम रखने जा रही है। जानकारी के मुताबिक, मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड भारत के ग्राहकों के लिए अलग से sheinindia.in नाम से ऐप शुरू करेगी। बता दें कि चीन की शीन कंपनी को भारत में बैन कर दिया गया था। पिछले करीब तीन वर्षों से कंपनी पर बैन लगा था।

बजाज इलेक्ट्रिकल्स की चौथी तिमाही में मुनाफा 34% बढ़ा

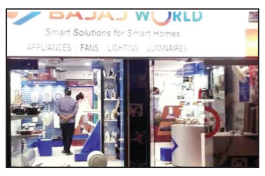

नईदिल्ली। बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने मंगलवार को बताया कि बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 34.08 फीसदी बढ़कर 51.85 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि एक साल पहले की इसी अवधि में उसका शुद्ध लाभ 38.67 करोड़ रुपये था। बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने बताया कि उसकी परिचालन आय बढ़कर 1,473.54 करोड़ रुपये हो गई, जो मार्च 2022 तिमाही में 1,293.26 करोड़ रुपये थी। इस दौरान कुल व्यय 1,442.73 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले इसी अवधि में 1,299.61 करोड़ रुपये था। बजाज इलेक्ट्रिकल्स की कुल आय मार्च 2023 तिमाही में 12.3 फीसदी बढ़कर 1,522.11 करोड़ रुपये हो गई।

इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की सब्सिडी में अचानक कटौती से प्रभावित होगा उद्योग

नईदिल्ली। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के निकाय एसएमईवी ने मंगलवार को कहा कि इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की सब्सिडी में अचानक कमी से भारी नुकसान हो सकता है। निकाय ने कहा कि इससे ईवी अपनाने में बड़ी गिरावट हो सकती है और पूरा उद्योग लंबे समय के लिए प्रभावित हो सकता है। हालांकि, दूसरी ओर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्र में स्टार्टअप कंपनियों ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि यह श्वङ्क उद्योग के लिए अपने दम पर खड़े होने का समय है। सरकार ने सोमवार को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर लागू फेम-2 योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को कम कर दिया था। यह फैसला एक जून 2023 को या उसके बाद पंजीकृत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर लागू होगा।

20 प्रतिशत टीसीएस का क्या है रहस्य

देवांशु दत्ता

विदेशों में क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर 20 प्रतिशत टीसीएस (स्रोत पर कर संग्रह) लगाने के साथ-साथ भारतीयों द्वारा विदेशी बैंक खातों में छह महीने से अधिक समय तक धन रखने पर प्रतिबंध लगाने से ऐसे संकेत मिलते हैं कि किसी ने विदेशी व्यय और बचत के तरीके की विस्तार से जांच की है। हालांकि, पहली नजर में ये उपाय ही भ्रमित करते हैं और दूसरी नजर में गौर करने पर लगभग समझ से परे हो जाते हैं। ऐसे में इस तरह के सवाल उठते हैं कि क्या यह कदम विदेश यात्रा को रोकने के लिए उठाया गया है? या क्या यह कर चोरी करने वालों को इस दायरे में लाने के लिए है? क्या यह विदेशों में निवेश को हतोत्साहित करने (या शायद प्रोत्साहित करने के लिए) है? क्या इससे सरकारी खजाने के लिए एक बड़ा ब्याज मुक्त पूंजी प्रवाह होगा? इन सभी के जवाब नकारात्मक प्रतीत होते हैं।

सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो विदेशी मुद्रा वाले क्रेडिट कार्ड के साथ विदेश जाता हो और वह आयकर के दायरे से बाहर हो। टीसीएस के लागू होने से पहले ही 7 लाख रुपये के दायरे को देखते हुए इसकी गारंटी है।

इसके अलावा ऐसा कोई क्रेडिट-कार्ड लेनदेन भी नहीं है जो बैंकिंग और कर रिकॉर्ड में दिखाई नहीं देता है। भारत के बैंक खाते से विदेशी खाते में या विदेशी खाते से भारत के बैंक खाते में पूंजी मिलने की जानकारी स्वचालित तरीके से दर्ज हो जाती है। इसलिए, इन उपायों से कर चोरी करने वालों की पहचान नहीं की जा सकती है।

क्या इससे लोग यात्रा करना छोड़ देंगे? विदेश जाने वालों का एक बड़ा हिस्सा पढ़ाई करने या काम करने के लिए विदेश जाता।

बाकी में से कई विदेशों में काम करने वाले बच्चों के साथ उन पर आश्रित माता-पिता होते हैं जिनका खर्च उनके बच्चे उठाते हैं। पर्यटकों का समूह बेहद छोटा है और वे अतिरिक्त खर्च वहन कर सकते हैं।

सवाल यह भी है कि क्या यह लोगों को उच्च स्तर की जोखिम वाली परिसंपत्तियों में विदेशों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है? यदि आप उन लोगों को रोकते हैं जो विदेश में कमाते हैं और अपना पैसा बैंक जमा में रखते हैं (जो कम जोखिम वाला निवेश है) तो आप उन्हें उच्च जोखिम/उच्च रिटर्न साधनों की तलाश करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यह वास्तव में उन लोगों को प्रेरित नहीं करता है जो विदेश में इसलिए कमाते हैं ताकि वे स्वदेश भेज सकें। न ही यह आयात पर कटौती करता है, उदाहरण के लिए, एमेजॉन से लीगो किट ऑर्डर करने पर टीसीएस लागू नहीं होता है।

क्या इन उपायों से सरकारी खजाने के लिए एक बड़ा ब्याज मुक्त पूंजी प्रवाह होगा? विदेशी पर्यटकों ने पिछले वित्त वर्ष में लगभग 7 अरब डॉलर खर्च किए और भारतीय छात्रों ने 5 अरब डॉलर या उससे अधिक खर्च किए।

इसमें से अधिकांश क्रेडिट कार्ड पर नहीं होगा, या यह 7 लाख रुपये की सीमा से नीचे होगा। इस कुल खर्च का 20 फीसदी हिस्सा करीब 20,500 करोड़ रुपये है जो पांच दिनों के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह के बराबर है। अब 7 लाख रुपये के न्यूनतम स्तर को देखते हुए टीसीएस, एक दिन या उससे भी कम अवधि के जीएसटी संग्रह के बराबर होने की संभावना है।

यदि आप इस पर निगाह रखने के लिए अतिरिक्त खर्चों की कमी पूरा करते हैं तब याद रखें कि इसे आखिरकार वापस ही किया जाना है तब ऐसे में एकत्र की गई राशि वास्तव में परेशानी उठाने के लायक नहीं है।

ऐसे में यह पूछना लाजिमी है कि क्या कोई गुप्त एजेंडा है? मेरे सामने जो सबसे अजीब सा स्पष्टीकरण आया है, वह यह है कि यह आयकर अधिकारियों को टीसीएस के रिफंड का लाभ उठाने की अनुमति देगा ताकि उन्हें उस प्रक्रिया को तेजी से निपटाने के साथ ही कुछ 'चाय-पानी' का खर्च निकल आए। लेकिन इस पर विश्वास करना मुश्किल है क्योंकि सरकार गर्व से इस तथ्य को पेश करती है कि वह खुद को भारत की अब तक की सबसे कम भ्रष्ट सरकार मानती है।

अमेरिका के साथ रिश्तों में और मजबूती कैसे आए

प्रणब ढल सामंता

अमेरिका और भारत में आज जो राजनीतिक माहौल है, वह पिछले एक दशक में हुए बदलावों का नतीजा है। 9/11 आतंकवादी हमलों के बाद इस्लामिक आतंकवाद से मुकाबले के लिए दोनों करीब आए और आज चीन के रूप में अहम चुनौती का सामना करने के लिए दोनों साथ हैं। इस संघर्ष में सीमा विवाद से लेकर तकनीकी वर्चस्व की लड़ाई तक शामिल है। जिन हालात में दोनों देशों के रिश्तों में बदलाव आया है, वह भी महत्वपूर्ण है। लेकिन यह भी मानना होगा कि दोनों देशों के संबंधों में हुई प्रगति के बावजूद नौकरशाही की पुरानी सोच और बाधाएं बनी हुई हैं। चीन पर दांव- सोवियत संघ के विघटन के बाद भी भारत और अमेरिका एक-दूसरे से दूर-दूर रहे। इकलौती सुपर पावर के रूप में अमेरिका ने 1990 के दशक में चीन पर दांव लगाया। जो आर्थिक रूप से एकीकृत था, लेकिन जहां लोकतंत्र नहीं था। जहां कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही चलती थी। उस दौर में चीन ने पाकिस्तान जैसे सहयोगी देशों को आतंकवाद रोकने के लिए मजबूर नहीं किया, जो भारत में अशांति फैलाने के लिए इनका इस्तेमाल कर रहा था। चीन ने उन देशों के साथ भी रिश्ते मजबूत किए, जिन्हें अमेरिका 'दुष्ट देश' कहता है। उसने नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान को परमाणु हथियार बनाने में मदद दी। दूसरी ओर, शीत युद्ध के बाद 1998 में भारत के पोखरण-2 परमाणु परीक्षण और 2001 में अमेरिका में हुए 9/11 के हमलों ने दोनों पक्षों को नजदीक ला दिया।

ब्यूरोक्रेसी की बाधा-2000 के दशक में भारत और अमेरिका के बीच सामरिक संबंधों को लेकर असल पहल हुई। 2008 का यूएस-इंडिया असैन्य परमाणु समझौता उस प्रयास की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इससे नौकरशाह अपना रवैया बदलने को मजबूर हुए, लेकिन उनकी ओर से चुनौतियां खत्म नहीं हुईं। ब्यूरोक्रेसी ने सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ और दूसरे तकनीकी मुद्दे उठाकर बाधाएं खड़ी कीं। इसीलिए न्यूक्लियर और तकनीक के क्षेत्रों में दोनों के बीच सहयोग नहीं बढ़ पाया।

नया युग- नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार भारत ने अमेरिका के साथ मजबूत रिश्तों को राजनीतिक रूप से अपनाया। इस दौर में दोनों देशों के संबंधों में संतुलन आया। अमेरिका को इसका अहसास हो गया था कि चीन उसके बरक्स खड़ा हो रहा है। अब वह 1990 और 2000 के दशक की अकेली सुपर पावर नहीं रह गया है। अमेरिका ने चीन को लेकर एक गलतफहमी पाल रखी थी कि आर्थिक समृद्धि उसे लोकतंत्र की राह पर ले जाएगी। इससे भारत जैसे साझेदारों को लेकर उसका रवैया सही हुआ। आज अमेरिका को पता है कि उसे भारत से क्या उम्मीद करनी चाहिए। अमेरिका यह भी जानता है कि भू-राजनीति को लेकर नए अलायंस के लिए उसे सहयोगी देशों के हितों का भी खयाल रखना होगा। जैसे, भारत की हथियारों को लेकर रूस पर निर्भरता। भारत और अमेरिका समझ रहे हैं कि रक्षा क्षेत्र में सहयोग कितना जरूरी है क्योंकि इसका असर हिंद-प्रशांत की भू-राजनीति पर पड़ने वाला है, जहां चीन बेहद आक्रामक है। 2016 के राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम के जरिए अमेरिका ने भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार बनाया। लेकिन अमेरिकी विदेश विभाग के आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट में भारत को ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसी बराबरी नहीं दी गई। इसके चलते जीई फाइटर जेट इंजन जैसी चीजों की तकनीक के ट्रांसफर प्रॉसेस में देर होती है।

क्षेत्रीय क्षत्रपों के लिए चुनौती बन रही कांग्रेस

नीरजा चौधरी

कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस ने वापसी की है और जिस आसानी से नेतृत्व के संकट को संभाला है, उससे पता चलता है कि कांग्रेस अपनी पुरानी कुशलता को फिर से हासिल कर रही है। सिद्धरमैया मुख्यमंत्री पद के लिए स्वाभाविक पसंद थे, जो पूरे कर्नाटक में बहुत ज्यादा स्वीकार्य थे और ओबीसी, मुस्लिम एवं दलितों से बने पुराने %अहिंदा% वोट बैंक का चेहरा थे। डीके शिवकुमार अपनी सीमाएं जानते थे और कड़ी सौदेबाजी के बाद दूसरे नंबर के पद के लिए मान गए-उन्होंने सत्ता साझेदारी के सबसे बेहतर के लिए सौदेबाजी की, जो काम कर गई। अब सबकी निगाहें इस बात पर लगी हैं कि दोनों कैसे मिलकर काम करते हैं और राज्य को सुशासन प्रदान करते हैं, जिसके लिए लोगों ने उन्हें चुना है। क्या कर्नाटक के नतीजे का असर इस वर्ष बाद में होने वाले राज्य चुनावों पर पड़ेगा? और 2024 में नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए पूरे विपक्ष को एक साथ लाने में वह किस हद तक मददगार हो सकता है?

कर्नाटक की जीत से कांग्रेस को मदद मिलेगी, क्योंकि इसने हताश पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार किया है, जो हिमाचल प्रदेश की जीत से पहले भूल गए थे कि चुनावी जीत का स्वाद कैसा हो सकता है। लेकिन कर्नाटक की जीत राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवाद की आग बुझा देगी, ऐसा असंभव है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अच्छी स्थिति में है, लेकिन कर्नाटक जीत के कारण नहीं, बल्कि मामा जी (चौहान) के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर के कारण। इसके अलावा, मध्य प्रदेश भाजपा में मतभेद हैं, जैसा कि कर्नाटक में भी था।

कहा जा रहा है कि अभी छत्तीसगढ़ में 50 = 50 फीसदी की स्थिति है। राजस्थान के विपरीत वहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल टीएस बाबा को प्रभावी ढंग

से किनारे लगाने में कामयाब रहे, जिन्हें हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियां मनाते देखा गया! भाजपा यहां भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है और यह अभी मालूम नहीं है कि शराब घोटाले की ईडी-जांच किस हद तक बघेल और उनके बेटे को प्रभावित करेगी, और भाजपा उससे कैसा लाभ उठाएगी।

भूपेश बघेल ने गरीब समर्थक उपाय किए हैं, जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसानों के लिए गरीब परिवारों से दो रुपये प्रति किलोग्राम गोबर खरीदना, बायोगैस के लिए इसका उपयोग करना, गरीब परिवारों की आय बढ़ाने में मदद करना, जो उनके पक्ष में जाता है। इसके अलावा उन्होंने क्षेत्रीय पहचान का छत्तीसगढ़िया कार्ड भी खेला है तथा राज्य के सांस्कृतिक विरासत को नरम हिंदू प्रतीकों जैसे राम वन गमन पथ से जोड़ा है। बघेल पिछले पांच वर्षों में ज्यादा मजबूत होकर उभरे हैं और अगर वहां कांग्रेस फिर से जीतती है, तो इसे पार्टी की जीत से ज्यादा उनकी जीत के तौर पर देखा जाएगा। कर्नाटक की तरह आज छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के पास भरोसा करने लायक स्थानीय स्तर पर मजबूत नेतृत्व है। ऐसा भाजपा के साथ नहीं है, उसके पास राज्य में प्रभावी नेतृत्व का अभाव है और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कुछ कारणों से परिदृश्य से गायब हैं।

सैद्धांतिक रूप से कर्नाटक की जीत मल्लिकार्जुन खरगे (जिनका कर्नाटक की जीत के बाद कद बढ़ा है) को गहलोत और पायलट को सुलह के लिए एक साथ मेज पर बैठाने के लिए प्रेरित कर सकती है, ताकि आगामी चुनावों में सीटों के बंटवारे पर समझौता हो सके। हो सकता है, पायलट राजी भी हो जाएं, पर गहलोत के मानने की संभावना नहीं है। गहलोत और पायलट के बीच रिश्ते अस्वाभाविक रूप से कटु हो चुके हैं। माना जाता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने दोस्तों से कह रखा है कि जब तक वह हैं, पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे! वह जयपुर में पायलट के लिए रास्ता बनाने के बजाय गांधी परिवार की इच्छाओं की धज्जियां उड़ाने और पार्टी अध्यक्ष पद की पेशकश छोड़ने के लिए भी तैयार थे। ऐसी स्थिति में, राजस्थान में युद्धविराम की संभावना नहीं दिखती है और राज्य में इसके अपने परिणाम होंगे। लेकिन भाजपा भी विभाजित और भ्रमित है।

जहां तक विपक्षी एकता की बात है, तो कांग्रेस के साथ अपनी एकजुटता जताने के लिए बंगलूरू पहुंचे विपक्षी नेताओं में जानी-मानी हस्तियां थीं, लेकिन उनकी संख्या में कोई इजाफा नहीं हुआ। महत्वपूर्ण बात यह थी कि ममता बनर्जी शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंची थीं, हालांकि उन्होंने अपनी पार्टी से किसी को भेजा था। अखिलेश यादव भी नहीं पहुंचे थे। अरविंद केजरीवाल को आमंत्रित नहीं किया गया था। संकटग्रस्त केजरीवाल (सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी शक्तियों को केंद्र ने एक अध्यादेश के जरिये फिर से छीन लिया है) को कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों के समर्थन की जरूरत है। लेकिन नीतीश कुमार को छोड़कर, जिन्होंने उनका समर्थन किया है, विपक्ष की तरफ से वह समर्थन केजरीवाल को मिला नहीं है। कांग्रेस की जीत ने विपक्षी दलों में उम्मीद जगाई है। इसने यह दिखा दिया कि भाजपा को मोदी और शाह के लगातार प्रचार के बावजूद हराना संभव है। भाजपा ने बजरंग दल को बजरंगबली से जोड़कर चुनाव अभियान को हिंदूवादी मोड़ देने की कोशिश की, लेकिन इसमें से कुछ भी कारगर नहीं हुआ।

हालांकि कर्नाटक की जीत ने क्षेत्रीय क्षत्रपों को चिंता में भी डाल दिया है कि क्या कांग्रेस उनकी कीमत पर अपनी ताकत बढ़ाएगी। आखिरकार कर्नाटक में कांग्रेस को फायदा तो जद (एस) की कीमत पर ही मिला, क्योंकि मुस्लिम मतदाता आसानी से जद (एस) से कांग्रेस के पाले में चले गए। यही बात ममता, अखिलेश और केजरीवाल के लिए भी चिंता का विषय है। विपक्षी गठबंधन के पक्ष में अल्पसंख्यक मतों को मजबूत करने के लिए यह उन्हें कांग्रेस के साथ गठबंधन करने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन इसे स्पष्ट करना होगा, क्योंकि हर पार्टी अब उत्साहपूर्वक अपने जनाधार की रखवाली कर रही है। इसलिए जब नीतीश कुमार सक्रिय रूप से एक राष्ट्रीय विपक्षी मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसे सिर्फ उसके सामान्य अर्थ में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यही क्षेत्रीय क्षत्रप अपने-अपने राज्य में कांग्रेस-या एक-दूसरे से जुड़ेंगे। कांग्रेस और विपक्षी दलों के लिए कर्नाटक की सीख यह है कि मजबूत स्थानीय नेतृत्व महत्वपूर्ण है तथा परिपक्व रवैये व देने-लेने की भावना से मतभेदों को सुलझाया जा सकता है।

कृपया इनसे सीखें — पहाड़ काट कर बनाई डेढ़ किलोमीटर सड़क

बृजेश बिष्ट

सरकार ने गाँवों को सड़कों से जोड़ने की कई योजनाएँ बनाई, पर कोई भी योजना मेरे गाँव तक नहीं पहुँच सकी। नेपाल सीमा से सटे उत्तराखण्ड के चंपावत जिले की लोहाघाट तहसील में मेरा गाँव है। मैं फौज में था और मुझे हर छुट्टी पर गाँव की नजदीकी मुख्य 7 सड़क से अपने घर तक पहुँचने के लिए एक बेहद मुश्किल संकरी पगडंडी का सहारा लेना पड़ता। मैं जितनी बार उस पगडंडी का प्रयोग करता, यही सोचता कि शायद अगली बार घर लौटने तक सरकार हमारी समस्या पर ध्यान देगी और गाँव तक एक अच्छी सड़क बन जाएगी। मेरे रिटायरमेंट के दिन करीब आ गए, पर वह वक्त नहीं आया। गाँव के पूर्व प्रधानों द्वारा कई मर्तबा इस सड़क के लिए प्रशासन और जन प्रतिनिधियों के पास कई प्रस्ताव भेजे गए, लेकिन किसी ने भी इन पर गौर नही किया। आखिरकार व्यवस्था से उम्मीद छोड़कर मैंने वर्ष 2014 में खुद ही अपने दम पर सड़क बनाने की सोची। उस समय मैं एक महीने की छुट्टी पर घर आया था। मैंने अपनी योजना गाँव वालों से साझा की, लेकिन कोई शख्स मेरे साथ नहीं आया। गाँव वालों की इस प्रतिक्रिया से मुझे थोड़ा दुःख तो हुआ, पर इससे सड़क बनाने के मेरे हौसले पर असर नहीं पड़ा और मैंने सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया।

पिछले साल सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद मैंने खुद को पूरी तरह इस काम में झोंक दिया। पहाड़ काट कर सड़क बनाने के पागलपन सरीखा काम शुरु करने के कारण मेरे परिवार वाले भी मुझसे नाराज रहने लगे। कई लोगों ने मेरे काम का मजाक भी बनाया। मगर मैंने किसी भी बात की परवाह नहीं की। सड़क बनाने की सफलता और मेरे बीच में पहाड़ था, तो मेरे इरादे भी किसी चट्टान से कम नहीं थे।

आज की महत्वपूर्ण घटनाएं

1981 टेक्सास के कॉर्पस क्रिस्टी शहर में एक अनाज की लिफ्ट में विस्फोट होने से 9 लोग मारे गए और 30 घायल हुए।
1986 मार्गरेट थैचर इजरायल का दौरा करने वाली ब्रिटेन की पहली प्रधानमंत्री बनी।
1991 इज़राइल रक्षा बलों ने ऑपरेशन सोलोमन शुरू किया, जो इथियोपिया के यहूदियों को इजरायल लाने के लिए एक आवरण था।
1993 इरिट्रिया ने इथियोपिया से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। इरिट्रिया में संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षणीय जनमत संग्रह के बाद जिसमें इरिट्रिया के लोगों ने स्वतंत्रता के लिए भारी मतदान किया, इरिट्रिया ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की।
1994 मीना (सऊदी अरब) में हज से जुड़े एक समारोह के समय भगदड़ मच जाने से 250 लोगों से भी अधिक हाजियों की मृत्यु।
2002 रूस और अमेरिका ने मास्को की संधि पर हस्ताक्षर किये।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

अक्ष्युपनिषद् (भाग-3)

गतांक से आगे...

जिन कृत्यों से किसी प्राणी को उत्तेजित न होना पड़े, ऐसे दया और उदारतापूर्ण सौम्य कर्मों को वह करता है। वह पाप से भयभीत रहता और भोग साधनों की अभिलाषा नहीं करता। वह ऐसी वाणी का प्रयोग करता है, जिसमें सहज स्नेह और प्रेम का प्राकट्य हो तथा जो मृदुल और औचित्यपूर्ण होने के साथ-साथ देश, काल, पात्र के अनुकूल हो ॥ 6-7 ॥

मनसा कर्मणा वाचा सज्जनानुपसेवते । यत: कुतश्चिदानीय नित्यं शास्त्राण्यवेक्षते ॥ 8 ॥

मन से, वचन से और कर्म से श्रेष्ठ पुरुषों का सत्संग करते हुए जहाँ कहीं से भी प्राप्त हो सके, प्रतिदिन सद्ग्रन्थों का अध्ययन करता है ॥ 8 ॥ तदासौ प्रथमामेकां प्राप्तो भवति भूमिकाम् । एवं विचारवान्य: स्यात्संसारोत्तारणं प्रति ॥ 9 ॥

स भूमिकावानित्युक्त: शेषस्त्वार्य इति स्मृत: । विचारनानीमितरामागतो योगभूमिकाम् ॥ 10 ॥ इस स्थिति में ही वह प्रथम भूमिका वाला कहलाता है। भवसागर से उस पार जाने की जो अभिलाषा करता है, वही इस प्रकार के विचार को प्राथमिकता देता है। वह भूमिकावान् कहा जाता है और शेष %आर्य% (दूसरों की तुलना में श्रेष्ठ) कहे जाते हैं। जो योग की दूसरी विचार भूमिका से युक्त हैं, उनके लक्षण इस प्रकार से हैं) । 9-10 ॥ श्रुतिस्मृतिसदाचारधारणाध्यानकर्मण: । मुख्यया व्याख्ययाख्यातायति श्रेष्ठपण्डितान् ॥ 11 ॥

वह ऐसे ख्यातिलब्ध श्रेष्ठ विद्वानों का आश्रय ग्रहण करता है, जो श्रुति, स्मृति, सदाचार, धारणा और ध्यान की उत्तम व्याख्या के लिए अधिक चर्चित हों ॥ 11 ॥ पदार्थप्रविभागज्ञ: कार्याकार्यविनिर्णयम्। जानात्यधिगतश्चान्यो गृहं गृहपतिर्यथा ॥ 12 ॥ मदाभिमानमात्सर्यलोभमोहातिशायिताम्। बहिरप्यास्थितामीषत्त्यजत्यहिरिव त्वचम् ॥ 13 ॥ इत्थंभूतमति: शास्त्रगुरुसज्जनसेवया । सरहस्यमशेषेण यथावदधिगच्छति ॥ 14 ॥

वह पदार्थों के विभाग और पद को उचित रीति से जानता है तथा श्रवण करने योग्य सत्शास्त्रों में पारंगत हो जाने पर कर्त्तव्य- अकर्त्तव्य के निर्णय में कुशल हो जाता है। मद, अहंकार, मात्सर्य, लोभ और मोहादि की अधिकता उसके चित्त को डाँवाडोल नहीं करती, बाह्य आचरण में यत्किंचित् यदि उसकी स्थिति रहती है,

क्रमश: ...

माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर

रेनू तिवारी

माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के दूसरे सरसंघचालक थे। गोलवलकर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सबसे प्रभावशाली और प्रमुख शख्सियतों में से एक माना जाता है। वह हिंदू राष्ट्र नामक एक सांस्कृतिक राष्ट्र की अवधारणा को सामने रखने वाले पहले व्यक्ति थे, जिनके बारे में माना जाता था कि यह अखंड भारत सिद्धांत, भारतीयों के लिए संयुक्त राष्ट्र की अवधारणा में विकसित हुआ था। गोलवलकर भारत के शुरुआती हिंदू राष्ट्रवादी विचारकों में से एक थे। गोलवलकर ने वी ओर आवर नेशनहुड डिफाइंड पुस्तक लिखी। बंच ऑफ थॉट्स उनके भाषणों का संकलन है। के.बी. हेडगेवार के बाद गोलवलकर 1940 से 1973 तक आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक (प्रमुख) बने रहे।

माधव सदाशिव गोलवलकर का जन्म 1906 में महाराष्ट्र नागपुर के पास के गांव रामटेक में हुआ था। माधव सदाशिव गोलवलकर के पिता का नाम सदाशिवराव और मां का नाम लक्ष्मीबाई था। माधव सदाशिव गोलवलकर का परिवार समृद्ध था और

उन्होंने उनकी पढ़ाई और गतिविधियों में उनका साथ दिया। गोलवलकर अपने नौ भाई-बहनों में एकमात्र जीवित पुत्र थे। अपनी आठ संतानों को खोने के बाद उनके माता पिता के लिए गोलवलकर काफी दुलारे थे। उन्हें ऐसा लगता था कि नियति ने किसी बड़े कार्य को करने के लिए ही जीवित रखा था। वे एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, नागपुर के हिसलोप कॉलेज से स्नातक डिग्री प्राप्त करने के बाद, उन्होंने विज्ञान में मास्टर डिग्री के लिए वाराणसी के हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। इस अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के संस्थापक और प्रतिष्ठित हिंदू नेता पंडित मदन मोहन मालवीय ने युवा माधव गोलवलकर को हिंदुओं के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। दिन प्रतिदिन उनका कद बढ़ता जा रहा था। अपनी युवा अवस्था के दौरान उन्होंने कॉलेज में एक प्रोफेसर के रूप में भी काम किया था। यहीं से उन्हें छात्रों ने गुरूजी कहना शुरू कर दिया था। बनारस में वह गुरूजी के नाम से ही मशहूर हो गये थे।

गोलवलकर ने संन्यासी बनने के लिए पश्चिम बंगाल में सरगाछी रामकृष्ण मिशन आश्रम के लिए अपनी वकालत और आरएसएस का काम छोड़ दिया। वह स्वामी अखंडानंद के शिष्य बन गए, जो रामकृष्ण के शिष्य और स्वामी विवेकानंद के भाई भिक्षु थे। 13 जनवरी 1937 को गोलवलकर ने कथित तौर पर दीक्षा प्राप्त की, लेकिन इसके तुरंत बाद आश्रम छोड़ दिया। 1937 में अपने गुरु की मृत्यु के बाद हेडगेवार की सलाह लेने के लिए वे अवसाद और अनिर्णय की स्थिति में नागपुर लौट आए, और हेडगेवार ने उन्हें आश्वस्त किया कि आरएसएस के लिए काम करके समाज के प्रति उनके दायित्व को सबसे अच्छा पूरा किया जा सकता है।

मोदी की पापुआ न्यू गिनी यात्रा का क्या है मकसद

हर्ष वी. पंत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी में जिस फोरम फॉर इंडिया-पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन की बैठक में भाग लेने जा रहे हैं, उसमें 18 प्रशांत द्वीपीय राष्ट्रों के नेताओं के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन भी शिरकत करने वाले थे। लेकिन वॉशिंगटन में चल रही डेट सीलिंग वार्ता के कारण बाइडन को अपना दौरा अचानक रद्द करना पड़ा। यह बैठक ऐसे समय हो रही है, जब दुनिया की प्रमुख शक्तियां हिंद-प्रशांत क्षेत्र के रणनीतिक समीकरण को नया आकार देने में लगी हैं।

चीन और अमेरिका के बीच उभरते भू-राजनीतिक विवादों में प्रशांत द्वीप समूह की केंद्रीय भूमिका पिछले काफी समय से स्पष्ट है। पेइचिंग 1980 के दशक से ही इस क्षेत्र के साथ आर्थिक रूप से जुड़ा रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में यह जुड़ाव सुरक्षा केंद्रित रिश्ते में तब्दील होता चला गया। पिछले साल चीन और सोलोमन द्वीप ने एक समझौता किया, जिसके मुताबिक पेइचिंग इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। इसमें ऐसे प्रावधान भी शामिल हैं जिनके तहत चीन वहां अपने जहाज भेज सकता है, रसद पहुंचा सकता है, यहां तक कि अपने कर्मचारियों और बड़े प्रॉजेक्टों की सुरक्षा के लिए बल का प्रयोग भी कर सकता है। अतीत में इस क्षेत्र में प्रभाव बनाने की होड़ चीन और ताइवान के बीच ही थी। लेकिन जैसे-जैसे चीन का आर्थिक दबदबा बढ़ता गया, ज्यादातर प्रशांत क्षेत्र के द्वीपीय राष्ट्र अपनी निष्ठा चीन को समर्पित करते गए। हालांकि स्थानीय स्तर पर असंतोष कम नहीं है। जैसा

कि इस क्षेत्र के कई वरिष्ठ नेता कहते हैं, हमारे देश के दीर्घकालिक हित- विकास की आकांक्षा, लोकतांत्रिक मूल्य, मानवाधिकार, कानून का शासन, मानवीय गरिमा और आपसी सम्मान- चीन के साथ जुड़ने में नहीं, ताइवान के साथ रहने में है। इसके बावजूद क्षेत्र में चीन का दबदबा लगातार बढ़ता ही रहा है। इसी साल फरवरी में दक्षिण प्रशांत देश मलाइता प्रांत के प्रमुख डेनियल सुइदानी को विधायिका ने पद से हटा दिया। सुइदानी इस देश में चीनी उपस्थिति के घोर विरोधी थे।

चीन-प्रशांत द्वीप समूह को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशटिव के लिहाज से खासा अहम मानता है और उसने प्रशांत द्वीप समूह फोरम (पीआईएफ) और चीन-प्रशांत द्वीप राष्ट्र आर्थिक विकास और सहयोग फोरम (ईडीसीएफ) जैसे क्षेत्रीय मंचों का असरदार ढंग से उपयोग भी किया है। हाल के वर्षों में चीन और दक्षिण प्रशांत के देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय बातचीत होती रही है। पिछले साल चीन के तत्कालीन विदेश मंत्री वांग यी ने दस प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ आर्थिक और सुरक्षा समझौता करने की काफी कोशिश की। इस प्रस्तावित समझौते को साझा विकास की पंचवर्षीय कार्य योजना कहा गया। हालांकि ये प्रयास सफल नहीं हुए, लेकिन इनसे इस क्षेत्र को लेकर चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षा जरूर रेखांकित हुई। इसके उलट, अमेरिका का रवैया इस मामले में बड़ा लचर रहा है। उसने कभी इन देशों के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता नहीं दी। नतीजा यह कि जैसे-जैसे इन इलाकों में चीन की पैठ बढ़ी, अमेरिका का असर कम होता गया। जो थोड़ा-बहुत जुड़ाव उसका रहा भी वह इस मायने में एकांगी कहा जाएगा कि उसकी दिलचस्पी सैन्य मौजूदगी तक सीमित रही। उसने इस क्षेत्र की विकास संबंधी जरूरतों पर कभी ध्यान नहीं दिया।

चीन की लगातार बढ़ती सक्रियता से आखिर अमेरिका की नींद टूटी। बाइडन के इंडो-पैसिफिक एक्सपर्ट कर्ट कैंपबेल ने आगाह किया कि प्रशांत क्षेत्र में चीनी सैन्य उपस्थिति से कभी स्थिति बिगड़ सकती है और इसलिए अमेरिका को भी यहां अपनी मौजूदगी बढ़ानी होगी। इसके बाद वाइट हाउस ने क्षेत्र में अमेरिकी राजनयिक उपस्थिति का विस्तार करने के लिए यूएस-पैसिफिक द्वीप रणनीति घोषित की और पिछले सितंबर में पहला यूएस-पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट किया, जिसने इस क्षेत्र को लेकर अमेरिका की प्रतिबद्धता दर्शाई। इसकी नौ-सूत्री घोषणा में यूएस-प्रशांत साझेदारी के लिए समर्थन, क्षेत्र में अमेरिकी क्षमता का निर्माण, सहयोगियों और साझेदारों के साथ समन्वय, जलवायु, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और समुद्री सहयोग, साइबर सुरक्षा, कनेक्टिविटी और कोविड-19 तथा स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ-साथ संघर्षों की विरासत को संभालना भी शामिल है। अमेरिका के इस अहसास ने कि इस इलाके पर उसके फोकस न करने के कारण ही चीन उस शून्य को भरने की स्थिति में आया, उसे क्षेत्रीय भागीदारों के साथ तालमेल बनाकर काम करने को प्रेरित किया है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और ब्रिटेन के साथ मिलकर अमेरिका ने पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक इनिशटिव लॉन्च किया जिसका मकसद पैसिफिक आइलैंड देशों को क्षेत्रवाद, संप्रभुता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व के सिद्धांतों के अनुरूप और प्रशांत द्वीप समूह की अगुआई व उनके निर्देशन में समर्थन उपलब्ध कराना है। इस समूह में एक ऑब्जर्वर के तौर पर भारत भी विकास में अहम भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली ने मोदी की फिजी यात्रा के दौरान 2014 में 14 प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एफआईपीआईसी लॉन्च किया था। तब से भारत ने नियमित उच्च स्तरीय बातचीत को बहाल रखने की कोशिश की है।

भले ही बाइडन की यात्रा रद्द हो गई, लेकिन मोदी के वहां रहते हुए पापुआ न्यू गिनी जाने की उनकी योजना अपने आप में एक स्पष्ट संदेश देती है। यह कि अमेरिका-भारत साझेदारी अब नए क्षेत्रों में नई संभावनाए तलाशने को लेकर किसी तरह की झिझक नहीं रखती और यह भी कि दोनों प्रशांत क्षेत्र में चीन के दबाव का एक प्रभावी विकल्प प्रदान करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। हालांकि, अमेरिका को जरूर अब यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी घरेलू समस्याएं उसे अपने सहयोगियों और साझेदारों को दीर्घकालिक रणनीतिक इरादों के संबंध में आश्वस्त रखने में बाधक न बनें।

बापू की दिनचर्या

रोगी-सेवा और चिकित्सा (भाग-4)

गतांक से आगे...

बापू बोले- मैं दोनों के पास चलूँगा और अत्यंत व्यस्तता के बावजूद समय निकालकर वे उन विकलांग भाइयों से मिले, उन्होंने उनको संतुष्ट किया। सन् 1915 में मद्रास की ओर घूमते समय बापू को अपने एक पुराने मित्र साथी के कुष्ठ से पीड़ित होने की खबर लगी। उन्होंने न केवल उनका पता लगाया, बल्कि अन्य कार्यों को छोड़कर वे उनकी सेवा में लग गए। उनकी स्थिति दयनीय थी। घावों से पीव निकल रही थी। बापू अपने हाथ से घाव धोते और उनकी परिचर्या करते। इसी प्रकार चंपारण (बिहार) में बापू के सहयोगी अनेक मजदूर सत्याग्रही जनों में से एक कुष्ठ से पैर सूजने तथा गिलटी निकल आने के कारण, उसे छिपाए हुए थे। एक दिन बापू तथा अन्य सत्याग्रहियों के साथ वे शिविर लौट रहे थे। फोड़ा फूट गया और मवाद तथा रक्त बहने लगा। अन्य साथी बना उनकी ओर ध्यान दिए जल्दी-जल्दी बापू के साथ आगे बढ़ गए। शिविर में पहुँचकर जब सायंकालीन प्रार्थना के समय सब लोग इकट्ठे हुए, तब बापू ने उन्हें वहाँ न देखकर उनके विषय में पूछा। कोई कुछ बता न सका। एक सज्जन ने इतना ही कहा कि जल्दी-जल्दी चलने में असमर्थ होने के कारण वे बीच में बैठ गए थे। यह सुनते ही बापू तुरंत उठ खड़े हुए और लालटेन लेकर उन्हें खोजने निकले। अन्य लोग भी बापू के साथ चलवे बेचारे एक वृक्ष के तले पड़े पीड़ा से कराह और राम-राम की रट लगा रहे थे। लालटेन का प्रकाश पड़ते ही वे चौंक उठे। बोले- अरे बापू! बापू बोले- भाई, क्या हुआ तुम्हें? तुमसे चला नहीं जाता था तो तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी? वे अवाक् थे। उन्होंने अपने पैर की ओर संकेत किया। पैर से रक्त बह रहा था। कुष्ठ रोग के भय से और लोग पीछे हट गए, किंतु बापू ने तुरंत अपना शाल फाड़कर घाव बाँधा और कंधे का सहारा देकर वे धीरे-धीरे उनको शिविर तक ले आए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने उनके पाँव और फोड़े को साफ किया, उस पर पट्टी बाँधी और उनको अपने पास बैठाकर तब उन्होंने सायंकालीन प्रार्थना की।

क्रमश: ...

संक्षिप्त समाचार

खाद्य मंत्री की अध्यक्षता में छग राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की बैठक 26 को

रायपुर। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की प्रथम बैठक 26 मई को दोपहर 12 बजे मंत्रालय, महानदी भवन स्थित समिति कक्ष एस-2-12 में आयोजित की गई है। बैठक में संबंधित विभागीय सचिव, प्रबंध संचालक राज्य विद्युत कम्पनी, सदस्य छत्तीसगढ़ भारतीय बीमा विनियामक प्राधिकरण, प्रबंधक लीड बैंक, दूरसंचार विभाग के निदेशक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के रजिस्ट्रार सहित अलग-अलग विभागों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे।

अनिमेष की जगह टंकराम भाजपा ग्रामीण के नये अध्यक्ष

रायपुर। पार्टी के अंदर चल रही अंतर कलह पर विराम लगाते हुए ग्रामीण जिला भाजपा अध्यक्ष अनिमेष कश्यप (बॉबी) को पार्टी ने अध्यक्ष पद से मुक्त करते हुए प्रदेश कार्यसमिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के रुप में रखा है। वहीं ग्रामीण अध्यक्ष के ओहदे पर टंकराम वर्मा की नियुक्ति की है जो अनिमेष कश्यप की जगह लेंगे। दूसरी ओर संगठन में फेरबदल करते हुए अशोक पांडे को प्रहलाद रजक की जगह जिला संगठन प्रभारी बनाया गया है। बताया गया कि अनिमेष कश्यप को काफी सक्रिय माना जाता रहा है, लेकिन उन्हें हटाने के पीछे पार्टी की अंदरूनी खींचतान को प्रमुख वजह बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि जिला प्रभारी प्रहलाद रजक से उनकी ठन गई थी। इससे परे गोढ़ी में पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव के दौरे के पहले विरोध प्रदर्शन के चलते उन्हें बदला गया है।

त्रिपाठी और ढिल्लन की रिमांड तीन दिन और बढ़ी

रायपुर। दो हजार करोड़ के शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार आबकारी विभाग के विशेष सचिव एपी त्रिपाठी और कारोबारी त्रिलोक ढिल्लन की रिमांड अवधि पूरी होने पर आज विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत में पेश किया गया। लंबी बहस के बाद दोनों को अदालत ने ईडी को तीन दिन की रिमांड पर फिर से सौंप दी है।

झारखंड से छत्तीसगढ़ में खपाई जा रही नशीली दवा, आरोपियों से माल बरामद

बलरामपुर। जिले की राजपुर पुलिस ने प्रतिबन्धित नशीली दवाओं का अवैध परिवहन करते 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. पुलिस ने आरोपियों के पास से नशीली दवाओं, कफ सिरफ इंजेक्शन और टैबलेट का जखीरा बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख 76 हजार बताई गई है। जानकारी के अनुसार, राजपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाओं का झारखण्ड के गढ़वा से अवैध परिवहन कर छत्तीसगढ़ के अन्य स्थानों पर बेचा जाता है. इस पर पुलिस ने एनएच 343 पर स्थित झींगों के सागौन जंगल के पास घेरा बंदी की। मुखबिर की सूचना के आधार पर बलरामपुर की ओर से राजपुर की ओर जा रही एक चार पहिया वाहन को पुलिस ने रोककर तलाशी ली. तलाशी के दौरान प्रतिबन्धित दवाओं को जब्त किया, जिसकी कीमत एक लाख 76 हजार रुपए बताई जा रही है. पुलिस ने चार पहिया वाहन को भी जब्त किया है, और तीनों आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

छत्तीसगढ़ में कम हुई कोरोना की रफ्तार, मिले 24 नए मरीज

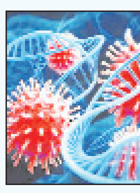

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना की संख्या में अब लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेशवासियों को कोरोना से काफी राहत मिली है। पिछले दिनों से कोरोना की रफ्तार थम गई है। वहीं प्रदेश में आज 2117 सैंपल की जांच हुई जिसमें 24 नए कोरोना संक्रमित मिले। अब प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 1.13 प्रतिशत है। मीडिया बुलेटिन के अनुसार कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज बलौदा बाजार और दंतेवाड़ा से 5-5 नए मामले सामने आया है। आज की दिनांक में कुल डिस्चार्ज की संख्या 44 है। पिछले 24 घंटे में प्रदेशभर में 24 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं प्रदेश में कुल एक्टिव केस 187 हैं। नए मरीज मिलने के बाद भी प्रदेश की सक्रिय कोरोना संक्रमित की संख्या घट गई है। प्रदेश के 8 जिलों में कोरोना संक्रमित पाए गए है। वहीं शेष जिलों में कोई मरीज नहीं मिला। प्रदेश में आज गौरेला पेंड्रा मरवाही से 1, जांजगीर-चांपा, दुर्ग, रायपुर से 2-2, धमतरी से 3, कांकेर से 4, बलौदा बाजार और दंतेवाड़ा से 5-5 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं।

आईटीआई भटगांव में दिया जाएगा असि. इलेक्ट्रिशियन का नि:शुल्क प्रशिक्षण

धमतरी। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जिले के युवाओं को धमतरी के भटगांव स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (आई.टी.आई.) में असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन कोर्स का नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए 18 से 45 साल तक की आयु के दसवीं कक्षा उत्तीर्ण युवा आगामी 30 मई तक आवेदन जमा कर सकते हैं। संस्था के प्राचार्य ने बताया कि तीन माह के इस प्रशिक्षण के दौरान सैद्धांतिक के साथ ही प्रायोगिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

झीरम कांड पर भाजपा कुछ छुपाना चाहती है : मुख्यमंत्री

भूपेश बघेल का केंद्र पर निशाना, कहा- नहीं लिए सरेंडर नक्सलियों के बयान

रायपुर। छत्तीसगढ़ के झीरम में 25 मई 2013 को हुए नक्सली हमले को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस हमले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने लावरवाही बरती है। जब प्रदेश सरकार ने जांच की डायरी मांगी, तो हमें नहीं दी गई। इस कांड के बारे में कुछ तो है, जिसे छुपाया जा रहा है। भाजपा कुछ तो दबाना और छुपाना चाह रही है।

मुख्यमंत्री ने रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा में सवाल करते हुए कहा कि हमारे पास इस घटना के पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन किसको दें? क्या उस एनआईए को दें, जिसने झीरम कांड के जीवित लोगों से पूछताछ नहीं की? क्या उस एनआईए से बात करें, जिससे राज्य सरकार ने जांच वापस मांगी, तो वो लोग हाईकोर्ट में चले गए, फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। वे लोग खुद जांच नहीं कर रहे हैं और न ही हमें जांच करने दे रहे हैं। बीजेपी को किस बात की डर है।

सीएम ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इसका क्या मतलब है। वह केस नहीं देना चाहते हैं। दो-तीन सवाल हैं। वहां से रोड ओपनिंग पार्टी हटाई क्यों गई? पूछ-पूछ कर क्यों मारा गया? पटेल कौन हैं? कर्मा कौन हैं? दिनेश पटेल कौन हैं? बंटी कर्मा कौन हैं? कभी आपने ऐसा करते देखा है कि नक्सली पूछ-पूछ कर मारते हैं? कभी ऐसा किए हैं? जब 4 बजे की घटना थी

तो सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? बहुत सारे सवाल हैं। फिर एनआईए की कोर्ट ने एनआईए को कहा कि जो नक्सली तेलंगाना में सरेंडर किए हैं, उनका बयान लिया जाए। एनआईए ने आज तक उनसे पूछताछ नहीं की, बयान नहीं लिया।

सीएम ने कहा कि इस मामले में जज का ट्रांसफर करा दिया गया। उसके घर में सुलती बम फेंका गया। उसे डराया धमकाया गया। तमाम मीडिया में यह खबरें रहीं। इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ दबाना-छुपाना चाहती है। इतनी बड़ी घटना थी, इसके बावजूद बीजेपी के नेता उटपटांग बयान दे रहे हैं। यह लोग निर्लज्ज हैं, इन्हें शर्म नहीं आती। इतने लोगों की जान चली गई। कांग्रेस नेताओं और जवानों की जान चली गई। उस पर ये राजनीति करते हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए यह भावनात्मक मामला है। वहीं एक कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को न्योता नहीं मिलने के सवाल पर कहा कि सबको निमंत्रण भेजा जाता है। यदि वे अतिरिक्त चाहते हैं, तो उन्हें अलग से निमंत्रण भेज दिया जाएगा।

25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस

बता दें कि 25 मई 2013 को बस्तर के झीरम घाटी में नक्सलियों ने हमला करके कांग्रेस नेताओं और सुरक्षाकर्मियों सहित 30 लोगों की हत्या कर दी थी। इस बार राज्य सरकार झीरम घाटी शहादत दिवस को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। जिसकी पूरे प्रदेश में तैयारी चल रही है।

झीरम घटना की फाइल राजभवन को क्यों दी, हमें दे : भूपेश

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मध्यप्रदेश प्रवास पर हैं। रवाना होने से पहले उन्होंने झीरम मामले की जांच को लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि, एनआईए ने जिंदा बचकर आए लोगों से पूछताछ नही की, एनआईए से हम लोगों ने कहा था कि, जो जांच की है, उसे सरकार को सौंप दें, लेकिन यह लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, आखिर बीजेपी को किस बात का डर सता रहा है। अगर एनआईए की जांच में कुछ नहीं निकला है तो उसकी कापी हमको दें, झीरम घटना की फाइलों को राजभवन में क्यों दे दिया गया। साथ ही कहा कि, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। यानी भाजपा कुछ न कुछ छुपाने में लगी हुई है। सीएम बघेल ने भाजपा पर तंस कसते हुए कहा कि, तेलंगाना में पकड़ाए नक्सलियों से एनआईए ने क्यों पूछताछ नहीं की? इस मामले की जांच करने वाले जज का ट्रांसफर क्यों करा दिया गया, इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि, भारतीय जनता पार्टी कुछ तो ऐसा है, जो छुपाना चाहती है। इस मसले को लेकर भाजपा बार- बार उटपटांग बयान दे रहे है। ऐसे निर्लज्ज लोग हैं, जिन्हें शर्म भी नहीं आती। झीरम हमले के वक्त इतने लोगों की जान चली गई और यह राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे।

वार्ड तीन में सड़क डामरीकरण कार्य का शुभारंभ कराया महापौर ने

कोरबा। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने वार्ड क्र. 03 में 68.93 लाख रूपये की लागत से किए जा रहे सड़क डामरीकरण कार्य का भूमिपूजन करते हुए कार्य का शुभारंभ कराया। इस मौके पर उन्होने पूरी गुणवत्ता के साथ डामरीकरण कार्य करते हुए समयसीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा वार्ड क्र. 03 के अंतर्गत विभिन्न सड़कों के डामरीकरण का कार्य 68.93 लाख रूपये की लागत से कराया जा रहा है। रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान महापौर प्रसाद ने मुख्य अतिथि के रूप में उक्त सड़क डामरीकरण कार्य का विधिवत भूमिपूजन किया व कार्य का शुभारंभ कराया। इस मौके पर महापौर प्रसाद ने कहा कि कोरबा शहर के सभी प्रमुख मार्गो व आवासीय तथा व्यवसायिक क्षेत्रों की सडकों की डामरीकरण, सड़कों का नवीनीकरण व जीर्णोद्धार के कार्य व्यापक पैमाने पर किए गए हैं, जो अभी निरंतर जारी हैं। कोरबा नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत सड़क संबंधी समस्त समस्याओं का सम्पूर्ण निदान किया गया है। महापौर प्रसाद ने आगे कहा कि नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा आमनागरिकों को मूलभूत सुविधाओं की निरंतर उपलब्धता की दिशा में व्यापक पैमाने पर कार्य हुए हैं, सड़कों के साथ-साथ पानी, बिजली, स्ट्रीट लाईट सहित अन्य मौलिक सुविधाओं की सहज उपलब्धता यहाँ के नागरिकों को सुगम रूप से प्राप्त हो रही है।

छत्तीसगढ़-तेलंगाना बॉर्डर पर 10 नक्सली गिरफ्तार

बीजापुर। छत्तीसगढ़-तेलंगाना बॉर्डर पर जवानों ने 10 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से ट्रैक्टर भरकर विस्फोटक बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक भरकर बड़े माओवादी लीडरों के पास ले जाया जा रहा था। यह भी सामने आया है कि इस विस्फोटक का इस्तेमाल छत्तीसगढ़ या फिर तेलंगाना में हमले के लिए होना था। यह इस साल के सबसे बड़े नक्सली हमले की तैयारी थी। पकड़े गए नक्सलियों में पांच बीजापुर के रहने वाले हैं। बॉर्डर इलाके में कार्रवाई तेलंगाना के भद्रादी कोत्तागुड़म पुलिस ने की है।

दुमुगुडेम मंडल में सर्चिंग अभियान चलाकर पकड़ा

तेलंगाना पुलिस की ओर से बताया गया कि, सूचना मिली थी कि नक्सली संगठन के सदस्य भारी मात्रा में विस्फोटक लेकर मुलाकानापल्ली और दुमुगुडेम मंडल के एक ठिकाने पर मौजूद हैं। इसके आधार पर भद्रादी कोत्तागुड़म पुलिस ने दुमुगुडेम पुलिस और छ्त्रक्क्न की 141वीं बटालियन के जवानों की एक टीम बनाई। इसके बाद जवानों ने इलाके के गांवों और उससे लगे जंगल में सर्चिंग अभियान चलाया। इसमें गांव के ही नजदीक 10 संदिग्धों को पकड़ लिया गया। उनकी निशानदेही पर भारी मात्रा में विस्फोटक

बरामद किया गया है।

500 डेटोनेटर, 90 बंडल कार्डेक्स वायर बरामद

पुलिस ने बताया कि बरामद सामान में एक ट्रैक्टर, एक बोलेरो वाहन समेत दो बाइक शामिल है। इन वाहनों की तलाशी लेने पर एक ट्रैक्टर भरकर विस्फोटक मिला है। इसमें करीब 90 बंडल कार्डेक्स वायर, 500 डेटोनेटर समेत अन्य विस्फोटक सामान बरामद हुआ। जिसके बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पता चला की इनमें से पांच आरोपी नक्सली तेलंगाना और पांच छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के पामेड़ इलाके के रहने वाले हैं। सभी आरोपी पिछले कई सालों से माओवादी संगठन के लिए काम कर रहे थे।

पूछताछ में और भी हुए खुलासे

गिरफ्तार नक्सलियों ने पुलिस को बताया कि ये सारा बारूद बड़े माओवादी लीडरों ने मंगवाया था। उन्हीं के पास लेकर जा रहे थे। इसका उपयोग किसी हमले के लिए किया जाना था। भद्रादी कोत्तागुड़म पुलिस ने बताया कि, इन सभी से पूछताछ में कई खुलासे भी हुए हैं। इनके पास से बरामद किए गए बारूद की कीमत लाखों में है। हालांकि, माओवादी ये विस्फोटक सामान कहां से लेकर आ रहे थे पुलिस ने इसका खुलासा नहीं किया है। असफरों ने कहा कि, जल्द ही माओवादियों के इस सप्लाई चेन को भी तोड़ा जाएगा।

इन नक्सलियों को किया गया गिरफ्तार

सममैया (36) निवासी- वारंगल
अरेपल्ली श्रीकांत (23) निवासी- वारंगल
मेकाला राजू (36) निवासी- वारंगल
रमेश कुम (28) निवासी- वारंगल
सल्लापल्ली (25) निवासी- वारंगल
मुचाकी रमेश (32) निवासी- बीजापुर
सुरेश (25) निवासी- बीजापुर
बाडसे लालू (22) निवासी- बीजापुर
सोडी महेश (20) निवासी- बीजापुर
मडवी चेतु (21) निवासी- बीजापुर

भाजपा किसान मोर्चा आयोजित करेगी जन चौपाल

बालोद। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला बालोद की बैठक कुर्मी भवन आयोजित की गई जिसमें आगामी 1 जून से 10 जून तक आयोजित जन चौपाल कार्यक्रम सहित अन्य संगठनात्मक रणनीति बनाई गई उक्त बैठक को कृष्ण कांत पवार अध्यक्ष भाजपा पवन साहू प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा भोजराज नाथ जिला सह प्रभारी भाजपा कोमल राजपुत प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा राजेश ताम्रकर प्रभारी लोहारा विधान सभा चुनेस्वर साहू जिला किसान मोर्चा प्रभारी केशव पटेल जिला सहप्रभारी किसान मोर्चा तोमन साहु ज़िला अध्यक्ष किसान मोर्चा की उपस्थिति मैं संपन्न हुआ इस बैठक जिला अध्यक्ष कृष्णकांत पवार ने कहा कि हम सब मिलकर ऐसे रणनीति बनाएं की भ्रष्ट प्रदेश सरकार प्रदेश सरकार की नीव हिल जाए जिला स प्रभारी भाजपा भोजराज नाग ने बैठक को संबोधित करते हुए कि किसानों लोक लुभावनी वादा करके कांग्रेसी सरकार बनाए हैं हम किसानों इनकी करतूतों को बता इस किसान विरोधी सरकार को प्रदेश से बेदखल करेंगे प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा पवन साहु ने कहा की किसान विरोधी कांग्रेस सरकार किसान विरोधी

कृत्य को बताने के लिए पूरे प्रदेश भर में जन चौपाल कार्यक्रम आयोजित है जिसमें बालोद जिले के सभी सोसाइटी में यह जन चौपाल कार्यक्रम आयोजित कर इस निकम्मी सरकार का विरोध कर भाजपा की सरकार बनाएंगे प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा कोमल सिंह राजपूत ने कहा कि लोक लुभावनी वादे करके कांग्रेस सरकार तो बना ली है लेकिन अपने वादे पूरे नहीं कर रही है खासकर किसान वर्ग शोषित एवं पीड़ित है जिसे न्याय दिलाना हमारा काम है जिला प्रभारी किसान मोर्चा चूनेश्वर साहू ने कहा कि यदि ऐसे भ्रष्ट सरकार के रहते सभी वर्ग मूलभूत सुविधाओं से वंचित है।

बैठक में जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा तोमन साहू ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि प्रदेश नेतृत्व के आवाहन पर आगामी 1 जून से 10 जून तक जिले के समस्त सोसाइटीओ में जन चौपाल अयोजित कर कांग्रेस सरकार की किसान विरोधी कार्य को उजागर करेगी इसी परिपेक्ष भाजपा व किसान मोर्चा की संयुक्त बैठक आयोजित की गई है सभी सभी जेस्ट श्रेष्ठ कार्यकर्ता गण इस जन चौपाल कार्यक्रम को सफल बनाएं

बैठक में कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी मंडलों के लिए प्रभारी सह प्रभारियों सभी सोसाइटी में जाने वाले वक्त भी तय की गई .बैठक का संचालन जिला महामंत्री हेमंत साहू एवं आभार प्रदर्शन जिला महामंत्री मनोहर सिन्हा द्वारा किया गया इस बैठक में प्रमुख रूप से प्रदेश कार्यसमिति सदस्य शालिक राम देशमुख टोमन साहू संतोष गंगबेद्यर विशाल मोटवानी जिला उपाध्यक्ष लीलाराम सोनबेर टीकाराम सांवरे जिला मंत्री धर्मेश साहू लाभार्थी प्रमुख मूरली साहू भोलाराम साहू देवलाल सिंहा राम स्वरूप यादव मंडल अध्यक्ष गण गणेश साहू पन्नालाल साहू सुरेश देशमुख दिनेश साहू चैतन्य निषाद प्रदीप साहू कन्हैया लाल यादव अमरजीत साहू बालमुकुंद वर्मा सहित भारतीय जनता पार्टी के जैसे इस कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे।

नागपुर मंडल में आज 8 घंटे का ट्रैफिक कम पॉवर ब्लॉक, नहीं होगा कोई ट्रेन रद्द

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले नागपुर मंडल के सौंदड़-देवलगांव के मध्य आरओबी लॉचिंग के चलते कल 24 मई को 8 घंटे का ट्रैफिक कम पॉवर ब्लॉक लिया जाएगा। हालांकि रेलवे प्रशासन ने किसी भी ट्रेन को रद्द या रिशेड्यूलिंग नहीं किया है।

रेलवे द्वारा द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास नवाचार, नेटवर्क क्षमता में विस्तार, माल ढुलाई विविधीकरण तथा अधोसंरचना विकास एवं वर्तमान समय में यात्रा करना सहज व रेलवे के उन्नत एवं व्यापक नेटवर्क तथा उसकी प्रतिबद्धता हेतू विभिन्न कार्य किए जा रहे है जिससे देश के विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर को भी बढ़ावा मिलेगा । जिसमे दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुये अधोसंरचना विकास के तहत विभिन्न स्टेशनों पर लगातार विकास कार्यों को पूरा करने हेतु हर संभव प्रयास कर रहा है । इस कड़ी में दिनांक 24-05-2023 को 8 घंटे (24-05-23 से रात 22.00 बजे से 25-05-23 के सुबह 06.00 बजे तक) का ट्रैफिक कम पावर ब्लाक लेकर सौंदड़-देवलगाँव के मध्य लेवल क्रॉसिंग गेट क्र. जीसीएफ़-27 को बंद कर इस के स्थान पर एलएचएस प्रस्तावित है इससे संबन्धित कार्य हेतु एलएचएस लांचिग कार्य किया जाना है ।

हादसों से बचने -बचाने के लिए रेल फाटकों को हटाना जरुरी है। रेल फाटक की जगह लो हाईट सब

वे तथा रोड ओवर ब्रिज बनाया वैकल्पिक मार्ग की सुविधा दी जा रही है । आने वाले दिनों में नागपुर मंडल में एक भी रेलवे फाटक नहीं होगा। अभिनव तरीके से संपादित किए जाने वाले इस कार्य के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर इस कार्य के दौरान किसी भी यात्री ट्रेन को कैंसिल,रेगुलेशन, रिशिड्यूलिंग, शॉर्ट टर्मिनेटिंग, डाइवर्जिंग नही किया जा रहा है । दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मण्डल के अंतर्गत यह कार्य गोंदिया-चांदाफोर्ट खंड पर सौंदड़-देवलगाँव के मध्य किया जायेगा और इस कार्य को बिना रेल सेवा बाधित किया जाएगा । इस कार्य में रेलवे का इंजीनियरिग विभाग, सिगनल एंड टेलिकाम विभाग, ऑपरेटिग विभाग, ट्रैक्शन विभागो सहित अन्य विभागों के रेलकर्मी संबधित कार्य करेंगे ताकि ब्लाक के समय अवधि के भीतर एलएचएस का लान्चिंग हो सके। एलएचएस का निर्माण होने से शहर के लोगों को रेलवे फाटक से निजात मिल जाएगा ।

जैवविविधता के संरक्षण और संवर्धन के लिए हो रहे सतत् कार्य : वनमंत्री

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस 22 मई 2023 के उपलक्ष्य में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के मुख्य आतिथ्य में नवा रायपुर स्थित अरण्य भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस के लिये इस वर्ष का थीम समझौते से कियान्वयन जैवविविधता को पुर्ननिर्माण था। इस अवसर पर राज्य जैवविविधता बोर्ड के अध्यक्ष श्री राकेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव (वन) श्री मनोज पिंगुआ, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री व्ही. श्रीनिवासराव, सदस्य सचिव श्री अरूण कुमार पाण्डेय तथा बड़ी संख्या में जैवविविधता पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रतिभागी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में राज्य स्तरीय जैवविविधता पुरस्कार 2023 की घोषणाएं की गई तथा

वनमंत्री श्री अकबर द्वारा चयनित संस्थाओं एवं व्यक्तियों को पुरस्कार वितरित किया गया। इनमें जैवविविधता प्रबंधन समिति धमनी बलौदाबाजार, श्री शिवकुमार चंद्रवंशी ग्राम कोको, माँ रूपई इको क्लब कसेकेरा महासमुंद, डॉ. जसमीत सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग, पीपुल फॉर एनिमल वाईल्ड लाईफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, कंजरवेशन कोर सोसायटी बिलासपुर, श्री वीरेन्द्र सिंह ग्रीन कमांडो जिला बालोद, डॉ विश्वनाथ पाणिग्रही बागबहरा, श्री अनुप रंजन पाण्डे, श्री राजवाडे ग्राम सोनपुरखुर्द को विभिन्न वर्गों में पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर सदस्य सचिव श्री अरूण कुमार पाण्डेय, वैज्ञानिक एम.एल. नायक, डॉ. आर.पी. मिश्रा द्वारा तैयार की गई पुस्तक %बायोडायवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़' का विमोचन भी वनमंत्री द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त जैवविविधता के क्षेत्र में जागरूकता लाने हेतु स्कूल व कॉलेज के छात्र-छात्राओं के लिए आयोजित ऑनलाईन निबंध पोस्टर एवं स्लोगन प्रतियोगिता के विजेताओं को भी मुख्य अतिथि के द्वारा पुरस्कार वितरण किया गया।

वन मंत्री श्री अकबर ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ जैव विविधता से परिपूर्ण है। यहां जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने राज्य में जैवविविधता संरक्षण तथा संवर्धन के प्रति एक जनजागरूकता अभियान प्रारंभ करने और इसे गति देने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में जैव विविधता समितियों को सक्रिय करने की दिशा में राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है।

कार्यक्रम को प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री व्ही. श्रीनिवास राव अध्यक्ष बायोडायवर्सिटी बोर्ड श्री राकेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव (वन) श्री मनोज पिंगुआ के द्वारा भी संबोधित किया गया।

कार्यक्रम के प्रारंभ में सर्वप्रथम जैवविविधता बोर्ड के सदस्य सचिव श्री अरूण कुमार पाण्डेय द्वारा बोर्ड की प्रत्येक वर्ष की गतिविधियों का संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण दिया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान सदस्य सचिव ने बताया कि बोर्ड के द्वारा राज्य में लगभग 12000 पी.बी.आर. (जन जैवविविधता पजी) तैयारी के लक्ष्य के विरूद्ध 8382 पी.बी.आर. तैयार कर ली गई है तथा यह कार्य सतृत रूप से चल रहा है। बोर्ड के द्वारा गिधवा परसदा क्षेत्र में एक पक्षी विवेचना एवं जागरूकता केन्द्र जो भविष्य में बर्ड सफारी के रूप में भी कार्य करेगा, बनाने का कार्य प्रगति पर है। प्रस्तावित बर्ड सफारी भवन की डिजाईन का भी प्रस्तुतीकरण सदस्य सचिव द्वारा किया गया।

गोठान बंजर, महीनों कोई नहीं आया: साव

मनरेगा का पैसा गोठान घोटाले की भेंट चढ़ गया: अजय चंद्राकर

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव चलबो गोठान खोलबो पोल अभियान के तहत आज कोंडागांव जिले के ग्राम बड़े कनेरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा गांव वालो ने बताया कि यहां 2 करोड़ रु खर्च किया गया है गोठान में बकरी पालन करने के लिए शेड भी बनाया गया है लेकिन यहां पर कोई गाय कोई जानवर नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहां पर महीनों से कोई नहीं आया होगा। उन्होंने कहा कि गोठान में गोबर की खरीदी की कोई व्यवस्था नहीं है और न ही किसी तरह की कोई गतिविधि संचालित हो रही है। गोठान में मछली पालन के लिए तालाब तो बनाया है लेकिन तालाब में पानी नहीं है। गायों के लिए चारे-पानी की भी व्यवस्था नहीं है, वर्मी कंपोस्ट बनाने वाली टंकी में बड़ी बड़ी घास उगी मिली। गोठान के बाहर गाय घूमती दिखी क्योंकि गोठान में कोई व्यवस्था नही थी।इस दौरान प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप, पूर्व मंत्री लता उसेंडी मौजूद रहे।

राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडेय भिलाई के कोसानाला में चलबो गोठान खोलबो पोल अभियान में शामिल हुई इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने यहां आनन-फानन में काम किया है जिसके कारण एक गौ माता की दुखद मृत्यु हो गई। गौठान में न चारा है और न ही पानी की कोई समुचित व्यवस्था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रायोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में कांग्रेसी कहते हैं कि वह गोबर बेचकर ट्रेक्टर खरीद लेता है तो कोई सोना खरीद लेता है। जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। छत्तीसगढ़ की पहचान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम के साथ घोटालों के रूप में एक मुख्यमंत्री की पहचान हो रही है। इस दौरान जब गौठान के बारे में आसपास के लोगों से पूछा गया तो बताया कि गौठान में चारे पानी की समुचित व्यवस्था भी नहीं है। उन्होंने कहा कि गोठान समिति के लोगों को पैसा भी नहीं मिल रहा है। प्रदेश सरकार की गोठान योजना की पोल जनता के सामने खुल चुकी है।

प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता, छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री व विधायक अजय चंद्राकर ने कुरुद के भखारा इलाके के तीन गोठानों का निरीक्षण किया तथा भारी गड़बड़ी पकड़ी। कुरुद विधायक श्री चंद्राकर ने ग्रामीणों से वस्तुस्थिति की जानकारी ली। ग्रामीणों की मौजूदगी में गोठानों की धांधली का भौतिक परीक्षण किया। गोठानों में गाय, गोबर, चारा, पानी कहीं नहीं दिखा।पूर्व पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि ग्राम पंचायतों से लेकर जनपद और जिला पंचायत के स्तर पर मूलभूत सुविधाओं का कोई काम भूपेश बघेल सरकार ने नहीं किया। ग्रामीण जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। पंचायतों का पैसा गोठान घोटाले की भेंट चढ़ गया है। इमनरेगा के पैसे का भी दुरुपयोग करते हुए गोठान घोटाले को अंजाम दिया गया है। मनरेगा में 60 फीसदी पैसा केंद्र सरकार देती है और 40 प्रतिशत पैसा राज्य सरकार का हिस्सा होता है। केंद्र सरकार के पैसे से जो काम होने चाहिए, वह नहीं हुए और मनरेगा की रकम गोठानों के निर्माण में लगा दी गई। इसके साथ ही 15 वें वित्त का पैसा भी घोटाले का शिकार हो गया। इन गोठानों में गाय और गोबर तो है ही नहीं।गायों के लिए चारा और पानी की व्यवस्था नहीं है। यह व्यवस्था इसलिए नहीं है क्योंकि गोठानों में गाय ही नहीं है।सारा पैसा भ्रष्ट हाथों में जा रहा है।इस दौरान बलौदाबाजार में विधायक शिवरतन शर्मा, छगन मुंदड़ा, बस्तर में बिलासपुर संभाग प्रभारी किरण देव, संतोष बाफना, लच्छुराम कश्यप, रूपसिंह मंडावी, कोंडगांव में सेवक राम नेताम, कमलचंद भंजदेव, दिनेश कश्यप सहित कई नेताओ ने अलग अलग गोठानों का निरीक्षण किया।

गौ हत्या के महापाप से मुक्त नहीं हो सकती भाजपा

रायपुर। पूर्व रमन सरकार के दौरान हुये 4400 करोड़ का शराब घोटाला, 1677.67 करोड़ का गौशाला अनुदान घोटाला, सरकारी जमीन पर बंदरबाट करने वाले पर कड़ी कार्यवाही की मांग करते हुये प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा प्रवक्ता एवं विधायक अजय चंद्राकर बताये रमन सरकार के दौरान गौशाला के नाम से जो अरबो का घोटाला और हजारों एकड़ सरकारी जमीनो का बंदरबाट एवं हजारों गायों निर्मम हत्या हुई एवं 4400 करोड़ के शराब घोटाला के दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी तो भाजपा न्यायालय जाकर जांच तो नही रुकवायेंगे? क्योंकि इसके पहले 36 हजार करोड़ के नान घोटाला और झीरम घाटी नक्सली षड्यंत्र हत्याकांड के आरोपी को बचाने भाजपा नेता धरमलाल कौशिक न्यायालय में जांच रुकवाने स्टे लाये जिसके कारण जांच बन्द हुई और आरोपियों को लाभ मिला। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा की भाजपा नेता कुछ भी बयानबाजी कर ले लेकिन गौ हत्या के महापाप से मुक्त नहीं हो सकते। 15 साल के रमन भाजपा शासनकाल में प्रदेश में 17000 से अधिक गोवंशों की निर्मम हत्या हुई है भूख से मौत हुई है दवा नही मिलने और सही समय पर उपचार नहीं होने से मौत हुई है और यह सब रमन सरकार के कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार के कारण हुआ है। गौमाता भूख से मर रही थी और भाजपा के नेता अपने गौशाला में गौमाता के अनुदान को डकार रहे थे। गौ माता के नाम से अरबों रुपए का भ्रष्टाचार रमन सरकार में हुआ सरकारी जमीनों का बंदरबांट हुआ लेकिन गौमाता को उसका लाभ नहीं मिल पाया गौ माता के नाम से भाजपा और संघ के नेता ही फलते फूलते रहे हैं।15 साल के रमन सरकार के दौरान उन चारागाह के जमीनों पर भाजपा और संघ के नेता कब्जा करके बड़े-बड़े बिल्डिंग बना लिए निजी उपयोग कर रहे और रमन सरकार ने मोटी रकम लेकर कुछ बड़े उद्योगपतियों को भी सरकारी चारागाह जमीन को दे दिया था।

बाबू भैया की कलम से

तब धान-नान अब गोबर-गौठान-गौशाला पर भी आरोप, हे प्रभु!

छत्तीसगढ़ में गोबर गौठान की राजनीति गर्माने लगी है। देश का पहला राज्य होगा जिसमें गोबर में भी विपक्षी दल ने घोटाला खोजने का काम शुरू कर दिया है। भाजपा ने यह बीड़ा सरकार के कार्यकाल के अंतिम वर्ष यानी चुनावी वर्ष में बड़ी शिद्दत से उठा लिया है। पूरे प्रदेश की हर विधानसभा में यह एक अभियान की तरह चल रहा है। बड़े छोटे सभी नेता कार्यकर्ता रोज एक या उससे अधिक गौठान में जा रहे हैं। कह रहे हैं कि यहां कोई व्यवस्था नहीं है,सब गड़बड़ी है। अखबारों में उनकी खिंचाई फ़ोटो के साथ समाचार भाजपा नेताओं के हवाले से छप रहे हैं। 1300 करोड़ के घोटाले का आंकलन भी कर लिया गया। आरोप भी इसी आंकड़े के साथ छत्तीसगढ़ सरकार पर चिपका दिया गया। मजेदार बात यह है कि साढ़े चार साल बाद ये आरोप चुनावी वर्ष में लगाए जा रहे हैं। कितना असर डालेंगें या नहीं डालेंगें इसका अनुमान लगाना भी अभी मुश्किल है। जानकार लोगों का कहना है कि देर हो गई है। यही काम भाजपा को दो वर्ष पहले ही शुरू कर लेना था। अब जनता इसे बहुत अधिक गंभीरता से लेगी, एसी संभावना जरा कम लगती है। कहा गया कि भाजपा की आदर्श संस्था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के "कुछ" सदस्य गोबर गौठान व गौवंश की रक्षा के लिए वर्तमान सरकार को धन्यवाद देने सशरीर सीएम हॉउस गए। उन्होंने सीएम से भेंटकर उन्हें सीधे इस कार्य के लिए बधाई दी थी। आरएसएस संस्था में एक बात तो है कि अच्छे को अच्छा व बुरे को बुरा बोलने का साहस है। जो सही करे वो उसे सही कह देते हैं। विचारों व संस्कृति की रक्षा के लिए समर्पित यह संस्था सही काम व बुरा काम में अपने पराए का भेद नहीं करती।अब ऐसा क्या हो गया कि इस चुनावी वर्ष में गौठान का काम खराब हो गया। शायद चार साल ठीक रहा होगा, इसलिए विपक्ष चुप रहा होगा। एकाध बार विधानसभा में किंचित प्रश्नोत्तरी में विरोध दर्ज जरूर किया गया ,लेकिन इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया , जिसकी चर्चा प्रदेश में या अखबारों में हुई हो। जो सद्गुण किसी सेवा भावी संस्था में होता है वह सदगुण राजनीति में नहीं होता। भाजपा ने जो तरीका अपनाया है, हमें तो लगता है कि यह फार्मूला कारगर भी हो सकता है। वह तब होगा जब जहां जहां गौठानों में बेहतर काम हो रहा है, उसकी तारीफ भी की जाए। साथ ही जहां खराब हो रहा है, वहां की आलोचना सकारात्मक ढंग से सरकार की आंख खोलने की शैली में हो। ताकि सरकार उस पर ध्यान दे सके, आम जनता पर असर भी हो। यह काम दो साल पहले किया जाता तो बहुत असर पड़ता। लोग कहते हैं कि विपक्ष अपनी सही भूमिका निभा रहा है। सकरात्मक प्रयास के बाद भी अगर अब तक खराबी वाले गौठानों में स्थिति नही सुधरती, तो आज के हो रहे प्रयासों में वजन होता। राजनीति के आसपास रहने वालों व उसे समझने वालों का मत है कि अनेक मुद्दों पर राजनीति करने के बाद विपक्ष ने समझ लिया कि शांति के टापू छतीसगढ़ में ये उग्र सोच वाले मुद्दे कम प्रभाव डाल रहे हैं। कर्नाटक चुनाव ने नया मुद्दा दिया है। सरकार का भ्रष्टाचार। विपक्ष ने कांग्रेस को इसी मुद्दे पर जब कर्नाटक के चुनाव जीतते देखा तो छतीसगढ़ में अपनी रणनीति बदल दी। अब भ्रष्टाचार मुद्दा बनाया है। जनता के सामने सरकार को बदनाम करने का साधन खोजना शुरू किया गया। ध्यान गोबर-गौठान पर आकर टिक गया है। रणनीति सही है। गोबर-गौठान पर सवाल उठा कर विपक्ष सही खेल खेल रहा है। देर से ही सही विपक्ष ने अब वर्तमान सरकार के गांव-गरीब-किसान व ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधार की सटीक राजनीति पर वार करना प्रारम्भ किया है। सफलता संदिग्ध भले ही हो पर रणनीति तो सटीक है। अखबारों में प्रचार का ढंग बदलना होगा। अपने नेताओं के खुद के बयानों व फ़ोटो के अखबारों में छपने का प्रभाव कम पड़ेगा। आये दिन टीवी डिबेट में आपको कांग्रेस के प्रवक्तागण छाती ठोक कर चुनौती दे रहे हैं कि हम चलते हैं आपके साथ , अगर कहीं भी घोटाला साबित हुआ तो वे इस्तीफा दे देंगे। उनकी चुनौती स्वीकार कर उन्हें बुलाइये उनके साथ जाकर दिखाइए कि कहां 1300 करोड़ की गड़बड़ी है। पत्रकारों को भी साथ ले जाइए आपके बयानों से नहीं जब स्वस्फूर्त अखबार नवीस देखेंगें और प्रतिनिधि के नजरिये से छपेगा तो ज्यादा सही व जनप्रभावी होगा। अन्यथा प्रदेश की जनता तो रोज आप लोगों के भ्रष्टाचार के आरोप प्रत्यारोपों को देख-सुन कर कन्फ्यूज़ हो ही रही है। सोचती है कि दोनों ही बेईमान हैं ,तो आखिर ईमानदार है कौन? एक खतरा भी है कि अगर जनता ने अपने मानस पटल पर यह बैठा लिया कि सभी अगर एक ही शैली से शासन चलाते हैं तो भ्रष्टाचार तो सामान्य बात हुई। तब क्या होगा जरा गंभीरता से सोचें।

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक 24 मई को

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा छत्तीसगढ़ की प्रदेश कार्यसमिति बैठक जिला भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर रायपुर में 24 मई 2023 बुधवार प्रात: 10:30 बजे आहूत की गई है जिसमे पूर्व में हुए कार्यक्रमों की समीक्षा एवं आगामी कार्ययोजना पर चर्चा होगी। प्रदेश कार्यसमिति बैठक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, मोर्चा प्रभारी डॉ सलीम राज, प्रदेश प्रभारी मोहम्मद सद्दाम, मोर्चा सह प्रभारी आरिफ खान एवं अन्य वरिष्ठ नेताओं की विशेष उपस्तिथि एवं अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद की अध्यक्षता में संपन्न होगी। इस बैठक में प्रदेश पधाधिकारी, संभाग प्रभारी सह प्रभारी, प्रदेश स्थाई आमंत्रित सदस्य गण, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य गण, प्रदेश विशेष आमंत्रित सदस्य गण, मोर्चा जिला अध्यक्ष एवं महामंत्री गण उस्पिथित रहेंगे।

ऑस्ट्रेलिया गई स्वास्थ्य मंत्री की टीम ने देखा ईएमआर सिस्टम

रायपुर। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री टी.एस. सिंहदेव के नेतृत्व में अध्ययन भ्रमण पर ऑस्ट्रेलिया गई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज गोल्ड कोस्ट यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के अधिकारियों के साथ अस्पताल की व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा की। टीम ने विगत 20 मई को क्वीसलैंड के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक गोल्ड कोस्ट यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का भ्रमण किया था। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव के साथ अध्ययन दौरे पर ऑस्ट्रेलिया गई टीम में स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री प्रसन्ना आर., स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक भीम सिंह, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक श्री भोसकर विलास संदिपान और राज्य नोडल अधिकारी डॉ. कमलेश जैन शामिल हैं।

टीम ने आज गोल्ड कोस्ट यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक कर वहां विकसित और लागू की गई ईएमआर (इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड) प्रणाली के बारे में जाना। हॉस्पिटल के अधिकारियों ने टीम के सामने इसका प्रस्तुतिकरण दिया। वहां के विशेषज्ञों ने अस्पताल की मजबूत आईटी सिस्टम का भी प्रेजेंटेशन दिया जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग होता है। इससे बीमारियों और केस लोड की संभावना की जानकारी

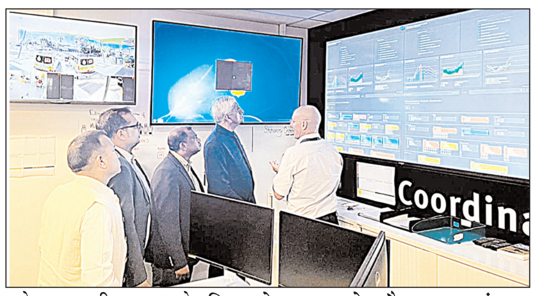

के साथ ही इलाज के लिए योजना बनाने और मानव संसाधन के प्रबंधन में मदद मिलती है।गोल्ड कोस्ट यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा राज्य से गए अध्ययन दल को वर्चुअल अस्पताल भी दिखाया गया, जहां मरीज अपने घर से ही वे सभी स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं जो वे अस्पताल में प्राप्त करते हैं। वर्चुअल अस्पताल द्वारा डॉक्टर से परामर्श, निदान एवं दवाएं मुहैया कराने के बाद जहां आवश्यक हो वहां स्टाफ नर्स या संबंधित स्वास्थ्य कर्मी द्वारा घर पहुंच सेवा भी प्रदान की जाती है। इससे रोगी का समय बचता है और अस्पताल में मरीजों का दबाव कम होने से दक्षता बढ़ती है।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

मुख्यमंत्री का भाषायी संतुलन बिगड़ना निंदनीय : भाजपा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा है कि लगातार सामने आ रहे घोटालों और भ्रष्टाचार के मद्देनजर आगामी चुनाव में अपनी सरकार की तयशुदा विदाई देखकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वे लगातार स्तरहीन बयान देकर अपनी राजनीतिक कुंठा का प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व मंत्री श्री मूणत ने 2 हजार के नोट चलन से बाहर करने के फैसले के बाद मुख्यमंत्री बघेल के 'थूककर चाटने' वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कालेधन के तौर पर जमा इन नोटों के चलन से बाहर होने पर कांग्रेस को हो रही तकलीफ जनता को समझ आ रही है। श्री मूणत ने कहा कि जिनकी तिजोरियों में 2000 के नोटों की शक्ल में इफरात काली कमाई भरी पड़ी है केवल वही भ्रष्ट लोग इस फैसले से आपा खो रहे हैं। तथाकथित स्वयंभू अर्थशास्त्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि भारतीय मुद्रा का भरोसा खत्म हो रहा है। मुख्यमंत्री का यह कथन देश की मुद्रा का अपमान है। भाजपा प्रवक्ता एवं पूर्व मंत्री श्री मूणत ने कहा कि दो हजार के नोट चलन से बाहर करने का फैसला तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है लेकिन पूर्ण शराबबंदी का वादा करके बघेल सरकार मुकर गई है, तो यह क्या है? युवाओं को रोजगार और दस लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता का वादा भी कांग्रेस ने किया।

राष्ट्रपति से कराये संसद भवन का लोकार्पण: मोहन मरकाम

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि संसद के नये भवन का लोकार्पण देश की महिला राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से आती है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के हाथों करवाया जाना चाहिये। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश की आधी आबादी महिलाओं के साथ देश की आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे में संसद भवन का लोकार्पण उनके हाथों से ही होना चाहिये। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मांग किया है कि राष्ट्रपति भवन का लोकार्पण राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के हाथों होना चाहिये। राष्ट्रपति देश की संविधानिक प्रमुख है। उनके हाथों संसद भवन का लोकार्पण संसद की गरिमा के अनुरूप भी होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आदिवासी वर्ग से है उनका केवल पद पर बैठना ही पर्याप्त नहीं है। राष्ट्रपति पद की गरिमा के अनुरूप उनका महत्व और सम्मान भी होना चाहिये। प्रधानमंत्री आत्ममुग्धता से बाहर निकल कर खुद पहल करके संसद भवन का लोकार्पण राष्ट्रपति को आमंत्रित करें। यह देश का आदिवासी समाज तथा महिलाओं की भावनायें है कि राष्ट्रपति के हाथों ही संसद की नई इमारत लोकर्पित हो, प्रजातंत्र में जनभावनायें सर्वोपरि होती है अत: केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को जनभावनाओं का सम्मान करना चाहिये।

आरक्षण और ओबीसी विरोधी मुख्यमंत्री डींगें न हांके-भाजपा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भाजपा पर ओबीसी विरोधी दृष्टिकोण अपनाने के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। श्री साव ने कहा कि ओबीसी वर्ग को लेकर कांग्रेस हमेशा दोमुँही बातें करती रही है और इस वर्ग का सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस ने ही किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर भी कांग्रेस सरकार ने ओबीसी वर्ग के अधिकारों पर डाका डालकर उनके साथ क्रूर खिलवाड़ किया। आरक्षण के मुद्दे को लेकर उसकी मुखालफत कर अदालत जाने वाले लोगों को खुद मुख्यमंत्री बघेल ने ऊंचे पद सौंपकर उपकृत व पुरस्कृत करने का कृत्य किया है। कांग्रेस का यह दोमुँहा चरित्र है। श्री साव ने कहा कि देश के समक्ष ऐसे अनेक अवसर आए जब भाजपा ने ओबीसी के हितों का पोषण किया। लेकिन कांग्रेस ने उसका विरोध करके अपनी क्षुद्र मानसिकता का प्रदर्शन किया। भाजपा की केंद्र में गठबंधन सरकार के समय ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने संबंधी विधेयक का कांग्रेस ने राज्यसभा में विरोध करके उसे पारित होने से रोकने की कोशिश की। विधेयक गिरा दिया था। इसी तरह भाजपा समर्थित बीपी सिंह की केंद्र सरकार ने पहली बार ओबीसी आरक्षण का प्रस्ताव रखा था, उसका भी विपक्ष में रहते कांग्रेस ने विरोध किया था। मूलत: कांग्रेस आरक्षण और ओबीसी विरोधी है।

ओडिशा के अधिकारियों ने ई-प्रोक्योरमेंट परियोजना का किया अवलोकन

रायपुर। आज यहाँ राजधानी रायपुर के सिविल लाईन्स स्थित कार्यालय में ओडिशा के 42 से अधिक राज्य सेवा के अधिकारियों ने चिप्स कार्यालय का भ्रमण किया। इन अधिकारियों को चिप्स द्वारा संचालित आई.टी. योजनाओं की जानकारी दी गयी। उक्त जानकारी देते हुए चिप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ शर्मा ने बताया कि शासकीय क्रय विक्रय के लिए संचालित एकीकृत ई-प्रोक्योरमेंट परियोजना द्वारा शासन की खरीदी-बिक्री में पारदर्शिता और मितव्यवता लाई जा रही है। इस परियोजना से राज्य के 56 विभाग, मंडल, निगम, बोर्ड जुड़े हुए हैं, जिनके प्रोक्योरमेंट से संबंधित समस्त कार्य एकीकृत ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। फलस्वरूप राज्य के बहुमूल्य समय और धन की बचत रही है। श्री अमिताभ शर्मा ने बताया कि यह परियोजना वैश्विक महामारी के दौरान अत्यंत उपयोगी रही, जिसके माध्यम से लॉकडाउन के बावजूद शासन को नागरिक सुविधा के लिए आवश्यक सामाग्रियों की खरीदी न्यूनतम दरों पर संभव हुई। इस अवसर पर चिप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ शर्मा के अलावा श्री अनिल पाठक, डिप्टी डायरेक्टर, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, श्री बिज्जू दत्ता, संयुक्त संचालक, वित्त, ओडिशा, श्री विवेक कुमार सिंह, संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वित्त एवं प्रशासन, चिप्स और परियोजना प्रमुख श्री प्रतीक पाण्डे भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

ओपन स्कूल हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल के परीक्षा परिणाम घोषित

रायपुर । छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के नतीजे आज घोषित किए गए। हाई स्कूल का परीक्षाफल प्रतिशत 54.09 तथा हायर सेकेण्डरी परीक्षा का परीक्षाफल प्रतिशत 65.46 रहा। हाई स्कूल परीक्षा में कुल 37 हजार 471 छात्रों का पंजीयन हुआ था। इस 34 हजार 161 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। 34 हजार 132 परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम जारी किया गया। कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थी 18 हजार 465 रहे। 29 परीक्षार्थियों का परीक्षाफल विभिन्न कारणों से रोका गया है। हाई स्कूल परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी में 4 हजार 13 परीक्षार्थी, द्वितीय श्रेणी में 7 हजार 320 विद्यार्थी तथा तृतीय श्रेणी 6 हजार 923 विद्यार्थी से उत्तीर्ण हुए। कुल 18 हजार 465 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इसी प्रकार हायर सेकेण्डरी परीक्षा में 65 हजार 557 विद्यार्थियों का पंजीयन हुआ था। इसमें 62 हजार 51 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। इनमें से 57 हजार 105 परीक्षार्थियों को परीक्षा परिणाम जारी किया गया। इनमें 9 हजार 653 परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी, 15 हजार 180 परीक्षार्थी द्वितीय श्रेणी से तथा 11 हजार 801 परीक्षार्थी तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। कुल 37 हजार 383 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। परीक्षा में 4 हजार 883 विद्यार्थी आरटीडी योजनांतर्गत अवसर परीक्षा में सम्मिलित हुए थे।

सभी के साथ जंगल में रहने वालों की भी चिंता जरूरी: मुख्यमंत्री बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मंगलवार शाम रायपुर में मृदा एवं जल संरक्षण विषय पर आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय परामर्शी कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित है लेकिन सभी के साथ जंगल में रहने वाली लोगों की चिंता भी जरूरी है।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि भू-जल स्तर पर्याप्त होना चाहिए। हमारी सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में नरवा योजना के अंतर्गत जल संरक्षण और जल संवर्धन के लिए वनांचल में 1 करोड़ 19 लाख संरचनाओं का निर्माण किया गया है। उन्होंने बताया कि भ्रमण के दौरान वे जहां भी गए सभी से इस योजना के संबंध में जानकारी ली, तो सभी का एक ही जवाब मिला नरवा

योजना अच्छी है। हर जगह आदिवासियों ने नरवा योजना को सराहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज गांव के लोग और वनसंरक्षकों की दोस्ती हो गई है। आदिवासी और वनांचल में रहने वाले लोग वन विभाग को अपना दुश्मन नहीं मानते। वन विभाग के अधिकारी जंगल जाते है तो लगता है, हमारे लिए कोई नई योजना आयी है, छत्तीसगढ़ में यह परिवर्तन आया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जंगल में ऐसे वृक्ष लगाएं जो वनांचल में रहने वालों के लिए लाभदायक हो। जंगल में फल देने वाले वृक्ष जरूर लगाने चाहिए। इसके साथ ही इनकी बिक्री की व्यवस्था भी होनी चाहिए। वन विभाग सिर्फ जंगल का अभिभावक नहीं बल्कि वहां रहने वाले लोगों का भी अभिभावक है। ऐसे आपसी संबंध विकसित करने में हम सफल रहे है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फलदार वृक्षों को बढ़ावा देने से आमदनी बढ़ेगी, हरियाली रहेगी और जंगल भी बचे रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के समय ऑक्सीजन के महत्व का पता चला। छत्तीसगढ़ से देश के कई इलाको में ऑक्सीजन पहुंचायी गयी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 67 प्रकार के लघु वनोपजों की खरीदी हो रही है। जिससे लघु वनोपज संग्राहकों को लाभ अर्जित हो रहा है।भारत सरकार में वन एवं पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव एवं महानिदेशक श्री चन्द्रप्रकाश गोयल ने मृदा एवं जल संरक्षण विषय पर आयोजित कार्यशाला में छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि अन्य राज्यों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में भूमि एवं जल संरक्षण में बेहतर कार्य हो रहा है। कार्यशाला में देश भर के वानिकी विशेषज्ञ शामिल हुए और छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित एवं सर्वंर्धित करने पर चर्चा हुई।

रेलवे स्टेशन में एनएसयूआई का प्रदर्शन

- **एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडेय के नेतृत्व में परेशान यात्रियों से संवाद करने पहुंचे एनएसयूआई कार्यकर्ता**

रायपुर। राजधानी रायपुर मे लगातार ट्रेनों के रद्द होने से यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. जिसको लेकर एनएसयूआई ने रायपुर रेलवे स्टेशन में प्रदर्शन किया जा रहा है. परेशान यात्रियों से एनएसयूआई नेताओं ने संवाद किया. इसके साथ ही टिकट की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की वहीं उन्होंने कहा कि ट्रेनों के कैंसिल होने से 7 दिन तक एनएसयूआई इसी प्रकार अभियान चलाएगी और अलग-अलग तरीके से प्रदर्शन करेगा। वही एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने कहा की लगातार ट्रेन रद्द हो जा रही हैं कल भी रेलवे बोर्ड ने 8 ट्रेनों को रद्द किया. इसके पहले भी लगातार सप्ताह

भर तक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहा है. कई हफ्ते तक ट्रेनें समय से नहीं आई घंटे ट्रेन लेट हुई। जिसको लेकर आज एनएसयूआई रायपुर के रेलवे स्टेशन पहुंचा और आम जनता से संवाद किया उनकी परेशानी जानी तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि एक से डेढ़ घंटा ट्रेन लेट चल रही हैं. समय पर अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पा रहे है. जिसको लेकर लगातार हमारा अभियान रेलवे स्टेशन में चल रहा है और एनएसयूआई ने यह तय किया है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.